



Sweating Locals For A Colonial Comfort

"You have the punkah in motion all day and all night somewhere, and for this purpose, you must have two men to relieve each other. When you go to bed ... you are fanned to sleep."

Killing Colonial Forest Policies

The Environmental Legacy of British Colonial Rule in India: A Lasting Impact on Wildlife and Ecosystems

सरकार अभी भी छोटी कमज़ोर पार्टियों की तलाश में जुटी है

मकसद है, इन पार्टियों को तोड़ कर किसी तरह, दो तिहाई वोट इकट्ठे किये जा सकें, जिससे संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जा सके

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। लोकसभा में चल रही तीखी और उच्च-स्तरीय बहस के बीच, जहां विपक्ष ने मिलकर नरेन्द्र मोदी सरकार पर चुनाव जीतने के उद्देश्य से लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कड़ा हमला किया, वहीं सरकार के मुख्य रणनीतिकार पदों के पीछे संख्या जुटाने में लगे हुए थे, ताकि दो-तिहाई बहुमत हासिल किया जा सके, जो फिलहाल सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है।

लोकसभा में मतदान कल शाम 4 बजे के लिए तय किया गया है, क्योंकि सदन आज देर तक चल रहा है।

सत्तारूढ़ दल के गृह मंत्री, जिन्हें दलों को तोड़ने वाले, और मुख्य चुनाव

■ सरकार को कुल 251 वोट मिले थे, विधेयक पेश करते समय तथा 290 वोट चाहिए, दो तिहाई बहुमत पाने के लिए। अतः फर्क इतना अधिक है कि यह संभावना बहुत कम है कि विपक्ष को तोड़ कर संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाया जा सके।

■ इस क्षीण संभावना के बावजूद सरकार, संविधान संशोधन विधेयक को वापस लेने के विकल्प के बारे में कतई सोच ही नहीं रही।

■ अतः, सरकार को महिला आरक्षण विधेयक का पारित न होना स्वीकार है, पर, वापस लेना स्वीकार नहीं। इसलिए छोटी-छोटी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास जारी है।

प्रबंधक व रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है, विपक्ष की कमज़ोर कड़ियों पर नज़र रखते हुए संख्या जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

लोकसभा का अंतर काफी बड़ा है और विपक्ष के लिए भाजपा की मदद करते हुए दिखना आसान नहीं है।

चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता को भी आंध्र प्रदेश में बड़ी राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर तब, जब पूरा दक्षिण भारत एक तरफ हो और वे दूसरी तरफ खड़े दिखें।

सवाल यह भी उठता है कि क्या

उनका समर्थन बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद में है, जो उन्हें भाजपा से मिल सकता है, या इसके पीछे कोई और कारण है, इसका जवाब केवल नायडू ही दे सकते हैं।

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा की अनदेखी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को 2026 की जाति जनगणना के आधार पर परिसीमन करने की मांग की, न कि पुराने आंकड़ों के आधार पर, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उनका हिस्सा नहीं मिल पाएगा।

उन्होंने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में

■ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से वार्ता में कहा, हम महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं, पर, पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे

सरकार का पूरा समर्थन करेगी, लेकिन पिछड़े वर्गों, दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर सहित, छोटे राज्यों के अधिकारों से वंचित करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी।

राहुल ने बताया कि सरकार 2011 की जनगणना पर जोर दे रही है, जिसमें ओबीसी से संबंधित कोई आंकड़ा है ही नहीं, और इससे उन्हें लोकसभा और विधानसभाओं में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का कारण समझाया

"महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का पुरुषों व किसी भी राज्य पर फर्क नहीं पड़े, इसके लिए लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 815 करना ही पड़ेगा

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में, केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, जो चल रहे विशेष सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण के महत्व पर बात की।

मोदी ने कहा, "जब से हमारे देश में महिला आरक्षण पर चर्चा शुरू हुई है और जब भी चुनाव हुए हैं, महिलाओं को लाभ देने का विरोध करने वालों को देश की महिलाओं ने कभी माफ नहीं किया।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत लोकतंत्र की जननी है। विकास की इस यात्रा में हमें एक नया आयाम जोड़ने का पवित्र अवसर मिला है।"

उन्होंने आगे कहा, "हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर

■ "और, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए नए ढंग से परिसीमन करना जरूरी है।"

■ पर, विपक्ष, प्र.मंत्री के तर्क को इतना तो स्वीकार करता है कि नए सिरे से सीटों का परिसीमन भी जरूरी है। पर, विपक्ष ने यह खामी निकाली है कि परिसीमन नई जनगणना के बाद होना चाहिए। क्योंकि, नये सेंसस में पहली बार निर्धारित हो जाएगा कि देश में ओबीसी की संख्या कितनी है, क्योंकि नये सेंसस में पहली बार, जातिगत जनगणना होगी और पहली बार आंकड़ा सामने आएगा कि देश में कितनी जातियाँ हैं और तब परिसीमन करना उचित होगा, क्योंकि तभी पूरी तरह से मालूम होगा कि किस चुनाव क्षेत्र में कितने बैकवर्ड हैं, आदि, आदि।

मिला है।"

कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्तावित संविधान (एक सी इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत कर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने परिसीमन विधेयक, 2026 भी पेश किया, जिससे विधायी निकायों

में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने पर चर्चा का मार्ग प्रशस्त हुआ

केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़कर 815 हो जाएगी, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश के उदाहरण से चौकन्ने हो गए हैं चंद्रबाबू नायडू

चंद्रबाबू नायडू ने न केवल अपने बेटे नारा लोकेश को टीडीपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, बल्कि संगठन में भी भारी बदलाव किया

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटने के कुछ ही दिनों के भीतर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद, चंद्रबाबू नायडू द्वारा अपने बेटे नारा लोकेश को टीडीपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना और संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करना कोई संयोग नहीं है। यह कदम पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव लाने की दिशा में उठाया गया है।

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने जेडीयू के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। उनके बेटे निशान्त हाल ही में राजनीति में आए हैं और अभी अनुभव हासिल कर रहे हैं। यह भी चर्चा का विषय है कि क्या वे अपने पिता की जगह ले पाएंगे। फिलहाल जेडीयू का संचालन कई वरिष्ठ

■ चंद्रबाबू ने सभी प्रमुख पदों पर अपने व अपने पुत्र के विश्वस्तों को नियुक्ति दी है तथा वरिष्ठ नेताओं को कम महत्व के पद दिए हैं।

■ नीतीश राज्यसभा में चले गए हैं, उनके पुत्र हाल ही में राजनीति में आए हैं, और इन हालात में जद (यू) के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है परन्तु चंद्रबाबू नायडू टीडीपी में यह हालात नहीं चाहते हैं।

■ विशेषज्ञों का कहना है, सिर्फ वे ही क्षेत्रीय दल, बड़े दलों के विस्तारवाद से खुद को बचा पाए हैं, जिन्होंने समय रहते ठोस उत्तराधिकार योजना बना ली थी, जैसे बिहार में राजद, तमिलनाडु में द्रमुक, यूपी में सपा और जिन दलों ने ऐसा नहीं किया, वे कमज़ोर हो गए हैं।

नेताओं, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, संजय कुमार झा, विजय कुमार चौधरी सहित, अन्य दिग्गज नेताओं द्वारा किया जा रहा है।

बिहार में जेडीयू के सहयोगी दल भाजपा पर अक्सर यह आरोप लगा रहा है कि वह अपने क्षेत्रीय सहयोगियों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रूस और ईरान से तेल खरीदने की छूट नहीं बढ़ाएगा अमेरिका

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान व रूस से तेल खरीदने की जो छूट दी थी, उसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। भारत इन छूटों का एक बड़ा

■ अमेरिका के ट्रेजरी सैक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, 11 मार्च से पहले जो तेल जहाजों पर लद चुका था, सिर्फ उसे बेचने की अनुमति थी, वो सारा तेल अब बिक चुका है।

लाभार्थी रहा है, क्योंकि इनके चलते नई दिल्ली को होमजुस्ट स्टेट के आसपास उत्पन्न व्यवधानों के बीच रूसी तेल की खरीद जारी रखने की अनुमति मिली थी। ट्रेजरी सैक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक तरफ ट्रंप वार्ता पुनः शुरु कराने के फायदे गिनाते-गिनाते थक गए हैं

दूसरी ओर उसके मंत्रिगण (सचिव लोग) ईरान को डराने-धमकाने का मौका खाली नहीं छोड़ते

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध के समाधान के लिए वार्ता फिर शुरू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच दोनों पक्ष फिर से टकराव की धमकी भी दे रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए वार्ता की मेज पर आने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पहले से भी अधिक कठोर हमले किए जाएंगे। हेगसेथ ने दावा किया कि नाकाबंदी प्रभावी रही है और इसने ईरानी बंदरगाहों से जहाजों को आवाजाही को रोक दिया है।

हेगसेथ ने यह भी कहा कि जो जहाज अमेरिकी नाकाबंदी का पालन नहीं करेंगे, उन्हें "रोका" जा सकता है, जिसका मतलब है कि अमेरिकी सेना उन जहाजों पर चढ़कर तलाशी और

■ अमेरिका के सैक्रेटरी ऑफ वॉर, पीट हेगसेथ ने ईरान को चेतावनी दी कि ईरान चुपचाप वार्ता करने टेबल पर आ जाए, अन्यथा अमेरिका की बमबारी ईरान में पहली बार से ज्यादा तबाही मचा देगी।

■ हेगसेथ ने यह कहा कि अमेरिका का "ब्लॉकैड" पूर्णतया सफल रहा है तथा अमेरिकी जहाजों ने चेतावनी प्रसारित की है कि अगर कोई जहाज ब्लॉकैड तोड़ कर निकलने की कोशिश करेगा तो अमेरिकी नौ सैनिक उन जहाजों पर जबर्न चढ़कर तलाशी लेंगे।

■ अमेरिका की शायद अब यह रणनीति है कि ईरान पर इतनी बमबारी करो कि ईरान की जनता तंग आकर ईरान की सरकार के खिलाफ बगावत कर दे, युद्ध समाप्त करवाने के लिए।

■ ईरान का स्टैंड, पश्चिमी देशों की इस सोच से काफी भिन्न है और वह भूखे पेट भी लड़ने को, मारने को तैयार है।

■ यह कुर्बानी की परम्परा पाश्चात्य सोच को अटपटी लगती है, जिसका उन्हें कोई जवाब नहीं दिखता।

जबकी कार्यवाही कर सकती है। अब तक कई जहाज अमेरिकी नौसेना की इस

चेतावनी के बाद वापस लौट चुके हैं। दूसरी ओर, ईरान अपने रख से

पीछे हटता नज़र नहीं आ रहा है और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चुनाव आयोग को अफसरों के तबादले का हक है'

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की तैयारी के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने जोर

■ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सत्ता की पुष्टि की और आयोग द्वारा अफसरों के तबादले करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

देकर कहा कि याचिका को खारिज किए जाने के बावजूद, इसमें उठाए गए कानूनी प्रश्न भविष्य में विचार के लिए खुले रहेंगे।

यह निर्णय कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें इन तबादलों को सही ठहराया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने हैं, जबकि मतगणना 4 मई को निर्धारित है।

कर्मचारी चयन बोर्ड की लेटलतीफी से 415 लोगों की नौकरियां अटकीं

कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड के ? सचिव को कई बार पत्र लिखकर "कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2024" का संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की है

-कार्यालय संवाददाता-

-जयपुर, 16 अप्रैल। राजस्थान

कर्मचारी चयन बोर्ड की लेटलतीफी के कारण 415 लोगों की नौकरियां अटकी हुई हैं। दरअसल "कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2024" भर्ती में 380 अपात्र पाए गए थे, जिसके बाद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर ने 4 अप्रैल 2026 को पत्र लिखकर संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन करीब 12 दिन बीतने के बावजूद यह परिणाम जारी नहीं हो सका। अब कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के वरिष्ठ शासन उप सचिव नरेश

गोकलानी ने 15 अप्रैल को राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को पत्र लिखकर इस परीक्षा का परिणाम तत्काल जारी करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि "कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2024" भर्ती में 380 अर्थव्यर्थियों ने विकल्प प्रस्तुत करके ऐच्छिक व्यवसाय/विषय का चयन किया और काउंसिलिंग में भाग लेकर अन्य पदों पर नियुक्तियां प्राप्त कर लीं। ऐसे में इन अर्थव्यर्थियों द्वारा अन्य व्यवसाय/विषय चुनने के कारण भी जो पद खाली हुए हैं, उन्हें भरने के लिए नए अर्थव्यर्थियों का चयन करते हुए बोर्ड की अनुशंसा भेजे

■ विभाग के मंत्री ने भी 9 अप्रैल को विभागीय बैठक में भर्ती प्रकरणों की देरी पर नाराज़गी जताई थी, पर, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ।

जाने का अनुरोध पूर्व में किया गया था, लेकिन आज दिन तक यह काम नहीं हुआ। पत्र में लिखा गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड "कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2024" भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करें, जिससे अपात्र पाए गए 35 लोगों की जगह भी नए लोगों को नौकरी मिल सके। इसके साथ ही अन्य विषय/व्यवसाय चुनने

वाले अर्थव्यर्थियों के कारण भी जो 380 पद रिक्त रह गए हैं, उन्हें भरने के लिए नए 380 चयनित अर्थव्यर्थियों के नाम भेजे जाएं, ताकि पात्र लोगों को नौकरी मिल सके।

पत्र में लिखा गया कि मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने भी गत 9 अप्रैल को विभागीय बैठक में भर्ती प्रकरणों की देरी पर नाराज़गी जताई थी। हैरानी की बात है

कि मंत्री की नाराज़गी के बावजूद, राज्य कर्मचारी चयन आयोग इस पूरे प्रकरण को दबाए बैठा है। सूत्रों का कहना है कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन सोशल मीडिया "एक्स" पर टिप्पणियां और पोस्ट साझा करने में मशगूल रहते हैं, लेकिन उनके विभाग की लापरवाही से 415 पात्र लोगों की नौकरियां अटकी हुई हैं, क्योंकि वे उसके लिए नए चयनित अर्थव्यर्थियों के नामों की अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। जबकि कौशल उद्यमिता विभाग और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर ने उन्हें कई बार पत्र लिखकर इस संबंध में कार्यवाही करने का आग्रह किया है।

स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की प्रतियां जलाईं

नामककल, 16 अप्रैल। द्रमुक प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज परिसीमन विधेयक, 2026 की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। संसद का विशेष सत्र आज शुरू हो रहा है। इस सत्र में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक, 2026 पेश किया जाना है।

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को विपक्षी दलों ने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। खास तौर पर, इस विधेयक के खिलाफ

■ उन्होंने पूरे तमिलनाडु में घरों पर काला झंडा फहराने का आह्वान किया।

द्रमुक प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शुरू से ही अपना कड़ा विरोध दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने इस विधेयक के विरोध में तमिलनाडु भर में घरों पर काला झंडा फहराने का आग्रह किया है।

नामककल जिले में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन ने काली शर्ट पहनकर ध्वजस्तंभ पर काला झंडा फहराया और परिसीमन विधेयक की प्रतियों को जलाकर, "लड़ेंगे, लड़ेंगे... तमिलनाडु लड़ेगा... जीतेंगे हम साथ मिलकर..." के नारे लगाए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु भर में विरोध की आग फैलने दो।

सरवाड़ डाई नदी क्षेत्र में बजरी खनन विवाद गहराया, लीजधारक बेबस

सरकारी नियमों के तहत लीजधारक द्वारा करीब 54 लाख 47 हजार 245 रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है

सरवाड़ (निर्स)। क्षेत्र की डाई नदी में बजरी खनन को लेकर वर्षों पुराना विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है वहीं वर्ष 2012 में पंकज सिंह जादौन के नाम से इस क्षेत्र में खनन लीज स्वीकृत हुई थी लेकिन उसी दौरान मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारधीन हो गया वहीं बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी खनन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए जिसके बाद वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए खनन का मार्ग प्रशस्त हुआ वहीं बताया जा रहा है कि 30 मार्च 2023 को पंकज सिंह जादौन ग्रुप के लोग जब सरवाड़ क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें नदी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया वहीं इस दौरान मारपीट व विवाद की स्थिति भी बनी जबकि सरकारी नियमों के तहत लीजधारक द्वारा करीब 54 लाख 47 हजार 245 रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है और सरकार द्वारा 433 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन लीज स्वीकृत की गई है। वहीं गोयला क्षेत्र के सनोदिया गांव में खसरा संख्या 175 पर करीब 73



सरवाड़ क्षेत्र की डाई नदी में बजरी खनन को लेकर वर्षों पुराना विवाद अब भी गहरा रहा है।

बीधा नदी क्षेत्र में लीज स्वीकृत है लेकिन यहां भी रॉयल्टी संचालक को बजरी निकालने नहीं दिया जा रहा वहीं संचालक वर्षों से तुलाई के लिए कांटा वजन मशीन लगाने का प्रयास कर रहा है वहीं लेकिन प्रशासनिक अन्देखी के चलते यह संभव नहीं हो पाया वहीं क्षेत्र में हालात ऐसे हैं कि वैध लीजधारक

खनन नहीं कर पा रहा जबकि अवैध खनन करने वाले माफिया खुलेआम सक्रिय हैं।

वहीं खिरिया गोयला अरबड़ जवाला सहित पूरे इलाके में दिन-रात जैसीबी और टैक्टरों के जरिए बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है वहीं सूत्रों के अनुसार अवैध खनन करने वाले लोग

सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए बजरी का स्टॉक सरकारी भूमि पर ही जमा कर रहे हैं ताकि कानूनी शिकंजे से बच सकें वहीं हैरानी की बात यह है कि यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं वहीं रॉयल्टी संचालक पिछले चार वर्षों से तहसीलदार थानेदार उपखंड

अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर तक जापन दे चुका है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई लगातार शिकायतों के बावजूद अवैध खनन पर रोक नहीं लगना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है वहीं क्षेत्र में भय का माहौल अवैध बजरी माफिया के बढ़ते प्रभाव के चलते पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है वहीं स्थानीय लोग खुलकर विरोध करने से कतराते हैं वहीं वैध लीजधारक भी खुद को असहाय महसूस कर रहा है वहीं जब सरकार को लाखों रुपये की राजस्व यि जमा हो चुकी है और लीज वैध रूप से स्वीकृत है तो आखिर वैध खनन क्यों बाधित है और अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सरवाड़ डाई नदी क्षेत्र में बजरी खनन को लेकर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है यदि समय रहते प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो यह विवाद और गहरा सकता है जरूरत है पारदर्शी कार्रवाई और वैध लीजधारकों को संरक्षण देने की ताकि सरकारी राजस्व की भी रक्षा हो सके और अवैध खनन पर लगाम लग सके।

पाठ्यपुस्तकें हटाने पर डोटासरा राजस्थान बोर्ड का बड़ा फैसला: कक्षा 9 से 12 तक की चार पुस्तकें सिलेबस से हटाई

जयपुर (हि.स.)। राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9 से 12 तक की चार पुस्तकों को पाठ्यक्रम से हटाने के निर्णय पर सियासी विवाद गहरा गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस फैसले को इतिहास पर सीधा हमला बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा कि कक्षा 9 की 'राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा', कक्षा 10 की 'राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति', कक्षा 11 की 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत' तथा कक्षा 12 की 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2' को हटाने नई पीढ़ी को अधूरा इतिहास पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम, देश निर्माण और विभिन्न नेताओं के योगदान का उल्लेख

है, जिसे हटाना इतिहास को मिटाने जैसा है। डोटासरा ने कहा कि यदि पुस्तकों में कोई त्रुटि थी तो उसमें संशोधन किया जा सकता था, लेकिन उन्हें पूरी तरह हटाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन पुस्तकों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह सहित कई नेताओं के योगदान, साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन है। डोटासरा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि इससे पहले भी आदिवासी वीरों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से जुड़े विषयों को पाठ्यक्रम से हटाया गया था और अब स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद के भारत के स्वर्णिम दौर को भी हटाया जा रहा है।

अवैध शराब से भरी कार जब्त

उदयपुर, (कासं)। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरी कार जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उप अधीक्षक राजीव राहट के सुपरविजन में खेरवाड़ा थानाधिकारी करनाराम जाट मय टीम ने नाकबन्दी के दौरान मुखबरी से मिली सूचना के आधार पर कार को रोक तलाशी ली तो उसमें डेढ़ लाख रूपये की अवैध शराब के 10 कार्टन मिले। इस पर कार सहित शराब जब्त कर चालक शेख अब्दुल रहमान पुत्र शेख अब्दुल कादर निवासी जुहापुरा वेंजलपुर अहमदाबाद गुजरात, साथी सतीश पुत्र रमेश निवासी बडला निचला फला खेरवाड़ा, रोहित पुत्र हाजाराण निवासी बडला निचला फला खेरवाड़ा को गिरफ्तार किया।

कि इन पुस्तकों को हटाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा भेजा गया था। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 11 अप्रैल के पत्र और समग्र शिक्षा के पूर्व आदेशों के आधार पर यह निर्णय किया है। नई व्यवस्था के तहत ये पुस्तकें अब पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रहेंगी।

इनमें कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं धरोहर, कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 11 की आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत - भाग 1 और कक्षा 12 की आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत - भाग 2 शामिल है। ये सभी पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में

थीं। निदेशालय ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इन पुस्तकों का अध्ययन किसी भी विद्यालय में नहीं कराया जाए। राजस्थान में कक्षा आठ तक का पाठ्यक्रम राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा तय किया जाता है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक का सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर निर्धारित करता है। इनकी सिफारिशों के आधार पर जयपुर स्थित पाठ्यपुस्तक मंडल पुस्तकों का प्रकाशन करता है।

ट्रेन की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक की मौत

निवाड़ी । झिलाया रोड पर स्थित कुंज बिहारी आश्रम के समीप रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी घासीराम मीणा ने बताया कि गौरव उर्फ गौर (21) पुत्र शिवदयाल जांगिड़ निवासी खंडवा गुरुवार को सुबह करीब साढ़े 10 बजे कुंज बिहारी आश्रम के समीप रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था।



गौरव

इसी दौरान वह जबलपुर-जयपुर वाली इन्टरसिटी ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गौरव राजकीय विद्यालय में फुटबॉल खेलते थे। घटना के बाद पत्नी को सूचना दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिवारों के सुपुर्द कर दिया।

और 108 पंखुलेंस की मदद से मृतक के क्षतविक्षत शव को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिवारों के सुपुर्द कर दिया।

नादोती एसडीएम सहित तीन कार्मिक 60 हजार की रिश्वत लेते पकड़े

आरोपियों के कब्जे से 4 लाख की संदिग्ध राशि भी जब्त

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की सवाई माधोपुर इकाई ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करौली जिले के नादोती उपखंड में एसडीएम सहित तीन कार्मिकों को 60 हजार रुपए की रिश्वत लेते रहे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान 4 लाख रुपए की संदिग्ध राशि भी बरामद की गई है। एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि उपखंड अधिकारी (एसडीएम) सुश्री काजल मीना, उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और वरिष्ठ सहायक प्रबन्धी धाकड़ को ट्रैप कार्रवाई में डिटोन किया गया है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने परिवादी से उसकी भूमि की फाइनल डिड्री जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने पहले एक लाख रुपए की मांग की थी और बाद में 50 हजार रुपए में



सौदा तय हुआ।

सत्यापन के दौरान रीडर दिनेश सैनी ने एसडीएम के लिए 50 हजार रुपए और अपने लिए 10 हजार रुपए की मांग की पुष्टि की। एसीबी टीम ने योजना के तहत



परिवादी को उपखंड कार्यालय नादोती बुलवाया, जहां रिश्वत की राशि 60 हजार रुपए ली गई। यह राशि रीडर दिनेश सैनी द्वारा लेकर वरिष्ठ सहायक प्रबन्धी धाकड़ को दे दी गई। इसी दौरान एसीबी टीम



ने मौके पर दोबारा देकर तीनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान प्रबन्धी धाकड़ के बैग से 60 हजार रुपए की रिश्वत राशि के साथ 4 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी भी बरामद हुई है। इस

अतिरिक्त राशि के संबंध में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक रिम्ता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला के निर्देशन में मामले की जांच जारी है। एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

हत्या के प्रयास का 37 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निर्स)। धंबोला थाना पुलिस ने 37 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी जिला पुलिस की टॉप-10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल था और उसकी गिरफ्तारी पर 1 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी लुट और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित था। धंबोला थाना अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भूरा उर्फ भूराका पुत्र पुना डामोर मीणा निवासी पलासडोर, थाना काकनवाणी, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) है। आरोपी वर्ष 1989 के एक मामले में डूंगरपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंट में वांछित था। उस पर लुट और हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।

लंबे समय से फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भूरा उर्फ भूराका को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी पर एक हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस मुखबिर तंत्र के माध्यम से उसकी पड़ताल कर रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस सदा कपडों में मौके

पर पहुंची और आरोपी को मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, जब टीम आरोपी को घर पहुंची तो उसने पुलिस को देखकर घबराकर गलत नाम और पता बताया।

हालांकि, सटीक मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जिले में लंबे समय से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

सरकारी स्कूल से गेट चोरी के आरोपी गिरफ्तार

कोटपुतली। निकटवर्ती सरुण्ड थाना पुलिस ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा से गेट चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया व लोहे का गेट बरामद किया है। थानाधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि गत 13 अप्रैल को परिवादी अशोक कुमार सुरेला (51) पुत्र जगदीश प्रसाद मेघवाल निवासी रायकरणपुरा थाना पनियाला हाल प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा ने दर्ज कराया कि अज्ञात चोर अवकाश के दिनों में सरकारी स्कूल में लगे लोहे के गेट को काटकर चोरी कर ले गये है। उक्त चोरी की वारदात का खुलासा करने हेतु थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर चोरी में संलिप्त आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम द्वारा लगातार आरोपियों की तलाश हेतु आसूचना एकरिज कर आरोपियों के मिलने वाले संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। बुधवार को संभावित स्थान ग्राम मोहनपुरा से आरोपी त्रिलोक (20) सचिन (19) दोनों निवासी मोहनपुरा, योगेश सुरेला (26) पुत्र श्याम लाल योगी निवासी जोधपुरा व विक्की (23) पुत्र सुन्दर लुहार निवासी बानसुर हाल पाटन को डिटोन कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया। चोरी किये गये लोहे के गेट को आरोपियों की निशानदेही से बरामद किया गया। चोरी के आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं में संलिप्तता व अन्य आरोपियों के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ की जा रही है।

कार की टक्कर से 55 वर्षीय महिला की मौत

निवाड़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी चोराहे पर सड़क पार करने के दौरान एक महिला के कार ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। बरौनी थानाधिकारी सुश्री कुसुम ने बताया कि मनभर देवी (55) पत्नी जगदीश जाट निवासी पहाड़ी अपनी पुत्री को जयपुर जाने वाली बस में बैठाने आई थी। अपनी पुत्री निकिता को बस में बैठाकर वह सड़क क्रॉस कर रही थी। कार चालक मौके से कार को लेकर फरार हो गया। सूचना पर बरौनी थाना पुलिस मय जापने के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मृतका का शव



मनभर देवी

कब्जे में लेकर निवाड़ी उप जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिवारों के सुपुर्द कर दिया। मृतक महिला के तीन पुत्रियां हैं।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, केकड़ी (अजमेर) राज.
 Email ID :- npeke@2011@gmail.com (0) : 01467-22002, 22019 web site : www.urban.rajasthan.gov.in/npeke
 क्रमांक : न.पा.के./मानव संसाधन/2026-27/156 दिनांक : 10/04/2026
 :- ई निविदा सूचना (04/2026-27)(NIB NUMBER - DLB2627A00445) :-
 एल्टर द्वारा है कि राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत पंजीकृत एनजीओ/संस्था/कर्म/अपरायर्स से निर्धारित प्रयत्न में ई प्रोप्रायोरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धित अधिक जानकारी वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है वरिष्ठ किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में आकर देखी जा सकती है।
 UBN No. 1: DLB2627SRR001355 अतिरिक्त अधिकारी नगरपालिका केकड़ी

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
 Website :- www.rajasthan.gov.in/ada, Tel.No. :- 0145-2627748-2627749
 क्रमांक :- अ.वि.दा./12/काकाकी/2026-27/काकाकी 21544817 दिनांक :- 13/04/2026
 :- ई निविदा सूचना संख्या 01/2026-27
 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की ओर से विभिन्न कार्यों की अनुमानित लागत राशि 986.32 लाख की ई-निविदा आम संख्या (1-2) दिनांक 07.05.2026 सायं 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट (http://eproc.rajasthan.gov.in) एवं (http://sppp.raj.nic.in) पर देखा जा सकता है।
 UBN : A:JD2627WLB000004, A:JD2627SLOB000005
 एल.एन.एल.टी/26/1918 अतिरिक्त अधिकारी नगरपालिका केकड़ी

कार्यालय नगरपालिका रतननगर (चूरू)
 फोन नं. :- 01562.294114 ईमेल:- mun_rnagar@yashoo.in
 क्रमांक : 102 दिनांक : 10/04/2026
 :- कार्यालय आदेश :-
 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4347-48 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा कराया संरक्षण हेतु टेंडर मय 01वीं अप्रैल 2026 रखाव सहित पर अनुबंध का कार्य जोन नं. 01 (वार्ड नं. 01 से 10) व जोन नं. 02 (वार्ड नं. 11 से 20) कार्य की जारी है-निविदा सूचना सं. 07 (2025-26) परिहराईय कार्यों से निरस्त की जाती है।
 सूचित रहे। अतिरिक्त अधिकारी नगरपालिका रतननगर(चूरू)
 राज.संवादा/सी/26/918

कार्यालय अधीक्षण अजयन्ता एवं परियोजना प्रबंधक वाटरशेड सेल कनड डेवेलपमेंट जिला परिषद जालौर
 क्रमांक :- एफ (1)/वि.वि.दा/2026-27/70-85 दिनांक :- 10/04/2026
 NOTICE INVITING BID
 NIT No. 01-16/2026-27
 Bids for NRM Works Under MISA-2.2 and PMSKY project area in Sayla, Jaswantpura, Sarnau, Chitalwana, Jalore, Ranivara, Sanchoore, and Bhnimal of estimated Value INR 809.32 Lacs are invited from interested bidders Up to 3.00 PM 20-04-2026. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal of the state.

NIT No.	Work Name & Block	NIB No.	UBN No.
NIT-01 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK SAYALA MISA 2 FARM POND AND ROOP TOP TANKA	WSC2627A0048	WSC2627WSRC00072
NIT-02 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK JASWANTPURA MISA 2 TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0049	WSC2627WSRC00073
NIT-03 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK SARNAU MISA 2 FARM POND AND ROOP TOP TANKA NIRMAN	WSC2627A0050	WSC2627WSRC00074
NIT-04 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK CHITALWANA MISA 2 FARM POND AND TANKA NIRMAN	WSC2627A0051	WSC2627WSRC00075
NIT-05 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK JALORE MISA 2 NADI, SUNKUN POND, KHADEEN, TANKA, ROOP TOP TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0052	WSC2627WSRC00076
NIT-06 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK JALORE MISA 2 KHADEEN, TANKA, ROOP TOP TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0053	WSC2627WSRC00077
NIT-07 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK RANIVARA TANKA NIRMAN	WSC2627A0057	WSC2627WSRC00080
NIT-08 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK RANIVARA ROOPTOP TANKA, FARM POND AND KHEEEN NIRMAN	WSC2627A0058	WSC2627WSRC00081
NIT-09 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK SANCHOORE ROOPTOP TANKA	WSC2627A0059	WSC2627WSRC00082
NIT-10 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK SANCHOORE ROOPTOP TANKA AND FARM POND	WSC2627A0060	WSC2627WSRC00083
NIT-11 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK SANCHOORE FARM POND NIRMAN	WSC2627A0061	WSC2627WSRC00084
NIT-12 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK CHITALWANA FARM POND AND TANKA	WSC2627A0062	WSC2627WSRC00085
NIT-13 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK BHINMAL ROOPTOP TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0063	WSC2627WSRC00086
NIT-14 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK BHINMAL ROOPTOP TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0064	WSC2627WSRC00087
NIT-15 /2025-26 MISA 2.2	BLOCK BHINMAL ROOP TOP TANKA AND FARM POND NIRMAN	WSC2627A0066	WSC2627WSRC00088
NIT-16 /2025-26 PMSKY 2.0	BLOCK SANCHOORE SUPPLY KHAJUR SET	WSC2627A0067	WSC2627GSR00089

2200 करोड़ रु. की जमीन पर कब्जा लेने गई हाऊसिंग बोर्ड टीम पर पथराव

बी-2 बाईपास से द्रव्यवती नदी तक 42 बीघा अवाप्तशुदा जमीन पर कब्जा लेने गई थी टीम

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। बीटू बाइपास से द्रव्यवती नदी तक 2200 करोड़ रुपए की 42 बीघा जमीन पर गुरुवार को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड की टीम कब्जा लेने गई थी। कब्जाधारियों ने हाऊसिंग बोर्ड टीम का विरोध किया और जेसीबी पर पत्थर फेंके। पथराव में किसी को चोट नहीं आई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाऊसिंग बोर्ड प्रशासन ने कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी।



अवाप्तशुदा जमीन पर कब्जा लेने पहुंची हाऊसिंग बोर्ड की टीम को विरोध झेलना पड़ा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उप-आवासन आयुक्त संजय शर्मा के नेतृत्व में टीम गुरुवार को दोपहर 3 बजे मौके पर जेसीबी मशीन लेकर पहुंची थी। यहां जेसीबी मशीन से जमीन पर बनी बांडूडी वॉल, कोठरियाँ और अन्य अतिक्रमणों के निर्माण को तोड़ना शुरू किया तो वहां रहने वाले कुछ लोगों ने विरोध जताया और हंगामा कर दिया। इस बीच वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने जेसीबी पर कुछ पत्थर फेंक दिए। इससे घबराए हाऊसिंग बोर्ड अधिकारियों ने कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक दी।

उप-आवासन आयुक्त संजय शर्मा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान हाऊसिंग बोर्ड की टीम पर पथराव जैसा कुछ नहीं हुआ। किसी को कोई चोट नहीं आई है। टीम ने कार्रवाई कर करीब 20 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाकर अपने कब्जे में ले लिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।

बीटू बाइपास चौराहे से द्रव्यवती नदी तक 42 बीघा से ज्यादा जमीन की हाऊसिंग बोर्ड प्रशासन ने वर्ष 1989 में अवाप्त करने की

प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 1991 में प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन तब कब्जा नहीं लिया गया। इस बीच जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति के पट्टे के आधार पर कॉलोनी बसा दी और भूखंड का बेचान दिखा दिया। ये बेचान वर्ष 1981 में जमीन खरीद के आधार पर बताया गया। बताया जा रहा है कि इसमें कई बड़े रसूखात लोगों को भूखंड कौंडियों के दाम बेचे गए।

वर्ष 2019 में कॉलोनी के नियमन को लेकर जेडीए ने एनओसी मांगी, लेकिन आवासन आयुक्त की जिम्मेदारी संभालते प्रकरण की जांच इनकार कर दिया। मंडल ने तर्क दिया कि जब जमीन पर 50 फीसदी निर्माण ही नहीं है तो नियमन क्यों किया जा रहा है? सोसाइटी के खिलाफ एफआई भी दर्ज करावाई गई। मामला एसीबी को भेज दिया गया। ग्राम चैनपुरा एवं

दुर्गापुरा की 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति ने सदस्यों के पक्ष में नियमितकरण की प्रक्रिया जेडीए में प्रारंभ कर दी थी।

वर्ष 2019 में हाऊसिंग बोर्ड भी जेडीए को इसके नियमितकरण के लिए एनओसी देने की तैयारी में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 भूखंडधारियों के मामले में यह निर्देश दिया था कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा सिविल न्यायालय में जमा कराई गई मुआवजा राशि बोर्ड को वापस लौटा दी जाए। तब पवन अरोड़ा ने हाऊसिंग बोर्ड आयुक्त की जिम्मेदारी संभालते प्रकरण की जांच कर एनओसी रोक दी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण (अवाप्त) को निरस्त नहीं किया था। इस आधार पर रईय याचिका भी दायर की गई।

गौरतलब है कि बी-2 बाइपास स्थित

■ **मौके पर काबिज लोगों ने हाऊसिंग बोर्ड के अफसरों का विरोध करते हुए जेसीबी पर पत्थर फेंके**

■ **राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाऊसिंग बोर्ड प्रशासन ने कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी**

श्रीराम कॉलोनी से जुड़ी विवादित करीब 42 बीघा जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने हाल ही में हाऊसिंग बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने जेडीए की ओर से 29 मई 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और इसके बाद के आदेशों को अवैध माना है।

31 जुलाई 1981 के समझौता विक्रय को भी अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। जस्टिस गणेश राम मोघा ने बोर्ड की याचिका मंजूर कर निजी पक्ष की 3 याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि संबंधित भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई बोर्ड के पक्ष में पूर्ण मानी जाएगी। समझौता विक्रय से स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता। धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश, भले वह अंतिम रूप ले चुका हो, वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि 12 फरवरी 2002 को एकलपीठ से गलत तथ्यों के आधार पर आदेश प्राप्त किया गया था, इसलिए रद्द किया जाता है।

राजस्थान चैस एसोिएशन के चुनाव पर लगी अंतरिम रोक हटी

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद्द किया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान चैस एसोिएशन के चुनाव पर एकलपीठ द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक हटा दी है। इस आदेश के बाद एसोिएशन के नए अध्यक्ष लक्ष्मण राठौड़, महासचिव विनेश कुमार शर्मा और कोषाध्यक्ष शैलेश गुप्ता का कार्यकाल शुरू होगा, जिसका चुनाव 4 मार्च 2026 को पूर्व में हो चुका है। इस मामले में याचिकाकर्ता राजस्थान चैस एसोिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलकाश शर्मा और सहायक अधिवक्ता अलंकृता शर्मा पेरवी के लिए पेश हुए थे। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाए।

इस मामले में पूर्व अध्यक्ष महावीर रांका के चयन के खिलाफ वर्ष 2021 में शिकायत सहकारिता रजिस्ट्रार को दर्ज हुई थी। उसी बीच तत्कालीन सचिव अशोक भागवत को हटाकर विनेश शर्मा को सचिव नियुक्ति करने का फैसला

बोर्ड मीटिंग में लिया गया। बाद में एक और शिकायत दर्ज हुई, जिसमें कहा गया कि, महावीर रांका को चुनाव नहीं लड़ना जांच के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिया। इस जांच अधिकारी को हटाए गए सचिव अशोक भागवत ने कुछ दस्तावेज दे दिए, जो कि उस समय सचिव के पद पर नहीं थे। इस घटनाक्रम के बीच 17 नवंबर 2024 को महावीर रांका व अशोक भागवत की ओर से रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पूछा गया कि, जब तक इस प्रकरण की जांच चल रही है, तब तक क्या चुनाव करावाए जा सकते हैं?

जबकि समिति का कार्यकाल सितंबर-2025 तक था। इस बीच रजिस्ट्रार की ओर से कहा गया कि, जांच पूरी होने तक चुनाव नहीं करावाए जा सकते। जब यह मामला हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष पहुंचा तो न्यायाधीश गणेशराम मीणा ने 25 फरवरी 2026 को आदेश दिए थे कि, एसोिएशन चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके

कैसर पीडित पत्नी के पति का तबादला आदेश पर रोक

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कैसर पीडित पत्नी के स्कूल व्याख्याता पति का तबादला करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है। वहीं अदालत ने अपीलार्थी को पूर्व की स्कूल से ही पद का वेतन देने को कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश गोपाल सिंह की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी उदयपुर के फतेह सूरजपीठ स्थित पोपम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता पद पर तैनात है। हाल ही में उसने एसआईआर की ड्यूटी पूरी की है और अब वह व्याख्याता पद का कार्यभार करना चाहता है। इस बीच विभाग ने उसका तबादला राजसमेत कर दिया। अपील में कहा गया कि अपीलार्थी की पत्नी ब्रेन ट्यूमर से पीडित है और बीते चार साल से उदयपुर में नियमित

■ **हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा**

■ **कोर्ट ने अपीलार्थी को पूर्व की स्कूल से ही पद का वेतन देने को कहा है।**

उपचार ले रही है। ऐसे में अपीलार्थी का तबादला करने से उसकी पत्नी का इलाज प्रभावित होगा। अपील में कहा गया कि अपीलार्थी के पद पर किसी अन्य को पदस्थापित नहीं किया गया है। इसके अलावा एकलपीठ ने याचिकाकर्ता सहित तबादलों से जुड़ी कई याचिकाओं को एक सामान्य आदेश से खारिज कर दिया था। इस दौरान याचिकाकर्ता के तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में अपीलार्थी के तबादले पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपीलार्थी के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।

सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय : मुख्यमंत्री

'अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से काम करेंगे तो आमजन को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा'



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष और कार्यकारिणी को शपथ दिलाई।

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय है, जहां से राज्य की सभी नीतियाँ एवं योजनाओं की शुरुआत कर आमजन को लाभान्वित किया जाता है। सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो सरकारी कामकाज में तेजी आती है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता है। शर्मा गुरुवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा और नवागठित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई कार्यकारिणी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाए।

■ **समयबद्ध पदोन्नति से 15 पद सृजित करने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने**

समारोह में मुख्यमंत्री ने समयबद्ध पदोन्नति से 15 और पद सृजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी जिन कैडर में पदोन्नति के लिये पूर्व में छूट नहीं मिल पाई, उनके लिये 2 वर्ष की छूट की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते सवा 2 साल में कार्मिकों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति दी जा रही है, प्रेच्युटी सीमा की 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख की गई है। आरजीएचएस में महिला-पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा

कि पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है, जो भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। अधिकारियों को रूल बेस्ट से रोल बेस्ट कार्यशैली की ओर अग्रसर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्मिकों के कल्याण के लिए अनुकूणा नियुक्ति के दायरे में पुत्रसभू को शामिल, एकल महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 6 चरणों में स्वीकृति तथा महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर एवं तनावमुक्त वातावरण देने के लिए "मुख्यमंत्री शिक्षा-वास्तव्य सदन" की स्थापना जैसे प्रावधान किए हैं। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित बड़ी संख्या में सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

सेफ्टी टैंक की दो कुई ढही, मलबे में दबे मजदूर की मौत

जयपुर। हरमाडा क्षेत्र में गुरुवार को दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की जान चली गई। बैनाड मेरुजी मंदिर के पास निर्माण कार्य के दौरान सेफ्टी टैंक की दो कुई ढहने से मजदूर मलबे में दब गया। देर तक चले रेस्क्यू के बाद उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब मजदूर टैंक के अंदर काम कर रहा था। अचानक कुई की दीवार भरभराकर गिर गई और वह मलबे में दब गया। इसी दौरान पास की दूसरी कुई भी ढह गई, जिससे मलबा और बढ गया तथा मजदूर पूरी तरह दब गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और सूचना पर हरमाडा थाना पुलिस व बचाव दल मौके पर पहुंचे। भारी मलबा हटाने में घंटों मशकत करनी पड़ी। कड़ी मेहनत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया।

सार-समाचार अनियंत्रित कार रैलिंग पर चढ़ी

जयपुर। राजधानी के गांधी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए रैलिंग पर चढ़ गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जखानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के अनुसार घटना सुबह गांधी नगर मोड़ पर हुई। तेज गति से आ रही कार अचानक अस्तव्यस्त हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद करीब 4 फीट ऊंची रैलिंग पर चढ़ गई। घटना के समय सड़क पर यातायात का दबाव कम होने के कारण अन्य वाहन इसकी चपेट में नहीं आए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कार चालक ने तत्पश्चात दिखते हुए क्रेन की सहायता से वाहन को रैलिंग से नीचे उतरवाया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारु कराया। थानाधिकारी भजन लाल ने बताया कि हादसे में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है, हालांकि कार क्षतिग्रस्त हुई है।

हाईकोर्ट ने उपायुक्त को तलब किया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में वकील की ओर से गंदगी के चलते बीमार होने का आरोप लगाने पर नगर निगम के मालवीय नगर जोन उपायुक्त को 28 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता विमल चौधरी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 31 मई, 2012 को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 16 बिंदुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से इन बिंदुओं की पाबनी नहीं की जा रही। याचिका में कहा गया कि बिरला मंदिर के पीछे गणेश नगर कॉलोनी में उनके निवास के आसपास काफी मात्रा में गंदगी है। जिसके चलते वे बीमार हो गए और दस दिन तक हाईकोर्ट में मुकदमों की पैरवी के लिए नहीं आ पाए। इसके अलावा वहां अवैध पार्किंग और पशु डेयरी भी चल रही है। नगर निगम को कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर अदालत ने स्थानीय जोन उपायुक्त को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

बीकानेर में ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विद्युत आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीकानेर स्थित 400 केवी जीएसएस की क्षमता को 630 एमवीए से बढ़ाकर 1130 एमवीए किया गया है, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति अब पहले से अधिक स्थिर, मजबूत और निरंतर हो सकेगी तथा अक्षय ऊर्जा की वीथी निकासी सुनिश्चित होगी। प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि बीकानेर के रायसर-जयपुर रोड स्थित 400 केवी जीएसएस पर 400/220 केवी, 500 एमवीए का नया ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया गया है। इसके संचालन से न केवल तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को अब बेहतर गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध होगी। बार-बार होने वाली वोल्टेज समस्या, ट्रिपिंग और लोड कटौती में उल्लेखनीय कमी आएगी। परियोजना के पूर्ण संचालन के बाद इस जीएसएस से जुड़े आसपास के 6 अन्य 220 केवी स्टेशनों पर भी लोड का संतुलन बेहतर होगा। इससे घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को अधिक निरंतर और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। विशेष रूप से बीकानेर एवं आस-पास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए यह अत्यंत अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। किसानों को सिंचाई हेतु नियमित एवं पर्याप्त विद्युत उपलब्ध होने से कृषि कार्यों में दक्षता बढ़ेगी एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।

उधारी के पैसे को लेकर खूनी संघर्ष

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुहाना इलाके में उधारी के पैसे को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। शांति बदमाश ने उधारी के पैसे देने का इत्तसा देकर युवक को बुलाया और उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश ने कार में ही चाकू से गला रेटा और पेट में चाकू धोने का प्रयास किया, परंतु गंभीर घायल होने के बाद भी युवक ने हिम्मत नहीं हारी और कार से नीचे उतर कर धर्मकांडे तक पहुंचा और अपने परिजनों को सूचना दी।

■ **मुहाना इलाके में हुई वारदात**

■ **पैसे लौटाने के लिए बुलाकर चाकू से चौर दिया पेट**

कराया। मेडिकल इत्तला पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बांस बिलवा निवासी गोविंद मीणा ने रामचंद्रपुरा निवासी गोविंद बाडेवाल को करीब 30 लाख रुपए उधार दे रखे थे। मंगलवार को बाडेवाल ने फोन कर

पैसे लौटाने की बात कही और गोविंद मीणा को लालबाग बुलाया। वहां मिलने के बाद आरोपी उसे अपने घर ले गया। इसका इस्तेफा देकर उसे पैसे दिलवाने का झांसा देकर उसे रिंग रोड की ओर ले जाने लगा।

रास्ते में आरोपी ने अपने साथी गिरधारी जाट को भी कार में बैठा लिया। सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही दोनों आरोपियों ने मिलकर गोविंद मीणा पर हमला कर दिया। बाडेवाल ने चाकू से उसकी गर्दन और पेट पर कई बार किए, जबकि पीछे बैठे गिरधारी जाट ने रस्सी से उसका गला घोटने का प्रयास किया। अचानक हुए इस हमले से युवक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन

उसने हिम्मत नहीं हारी। हमले के दौरान गोविंद किसी तरह कार से बाहर निकलकर जान बचाने के लिए भागा। वह लहलुहान हालत में पास के एक धर्मकांडे तक पहुंचा और अपने परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत मानसरोवर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मेडिकल इत्तला पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने गोविंद बाडेवाल और गिरधारी जाट के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

प्रदेश के 10 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण देगी सरकार

जयपुर में विश्वस्तरीय कौशल संस्थान एवं स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेगा

जयपुर। नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी) और राजस्थान सरकार मिलकर अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। इस प्रोजेक्ट का रोडमैप बनाने के लिए गुरुवार को जयपुर में 'राजस्थान स्टेट-एनएसडीसी सेक्टर रिक्त कार्डसिल कौशल संवाद' आयोजित किया गया। इस उच्चस्तरीय परामर्श कार्यशाला की सह-अध्यक्षता कौशल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा तथा एनएसडीसी के सीईओ अरुणकुमार पिल्लई ने किया। कार्यशाला में 28 सेक्टर स्किल कार्डसिल के सीईओ एवं वरिष्ठ अधिकारी, एनएसडीसी तथा आरएसएलडीसी की नेतृत्व टीमों ने भाग

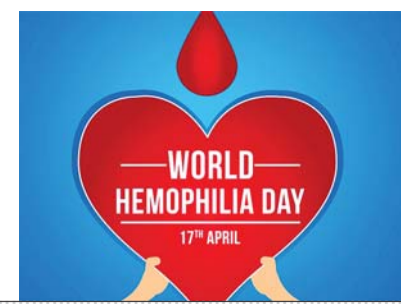


जयपुर में गुरुवार को 'राजस्थान स्टेट-एनएसडीसी सेक्टरस्किल कार्डसिल कौशल संवाद' कार्यक्रम आयोजित हुआ।

लिया। बैठक में चर्चा की गई कि, राजस्थान में प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों में पर्यटन, हरित ऊर्जा, रत्न एवं आभूषण, विनिर्माण तथा फूड प्रोसेसिंग शामिल हैं। ऐसे में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भविष्य की जरूरतों को देखते

एवं स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी) की स्थापना तथा 10-15 सेक्टरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओईएस) की स्थापना करने पर भी चर्चा की गई। युवनेस्वर के वर्ल्ड स्किल्स सेंटर एवं भीपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क की तर्ज पर इनका विकास होगा। इस परियोजना पर राजस्थान सरकार ने 450 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

बैठक में चर्चा हुई कि, प्रदेश में सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) जैसे उभरते क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। वर्ष 2030 तक राजस्थान में लगभग 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाना लक्ष्य है।



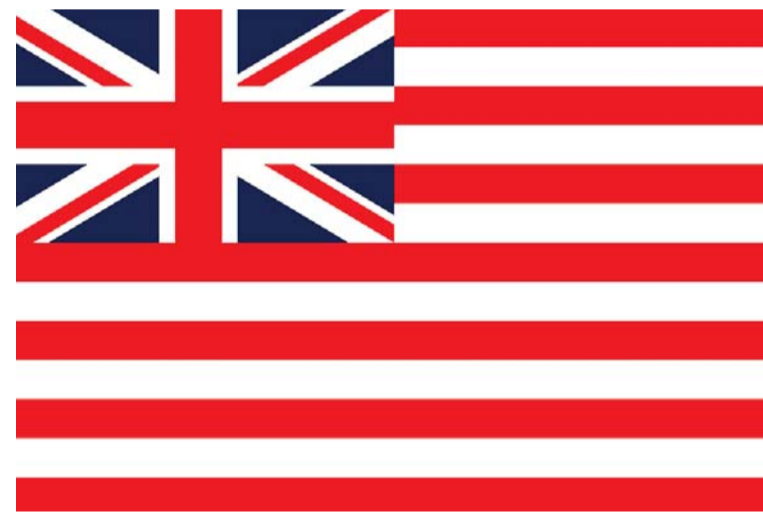
World Hemophilia Day: Raising Awareness for a Rare Bleeding Disorder

Observed annually on April 17, World Hemophilia Day aims to increase awareness about hemophilia and other inherited bleeding disorders. The day highlights the challenges faced by patients, including delayed diagnosis, limited access to treatment, and the high cost of care. Hemophilia, a genetic condition that impairs the blood's ability to clot, can lead to prolonged bleeding and serious health complications if untreated. Global health organisations and patient groups use this occasion to advocate for better healthcare policies, improved access to clotting factor therapies, and stronger community support, ensuring that those affected can lead healthier, more dignified lives.

#ENVIRONMENT

Killing Colonial Forest Policies

The Environmental Legacy of British Colonial Rule in India: A Lasting Impact on Wildlife and Ecosystems



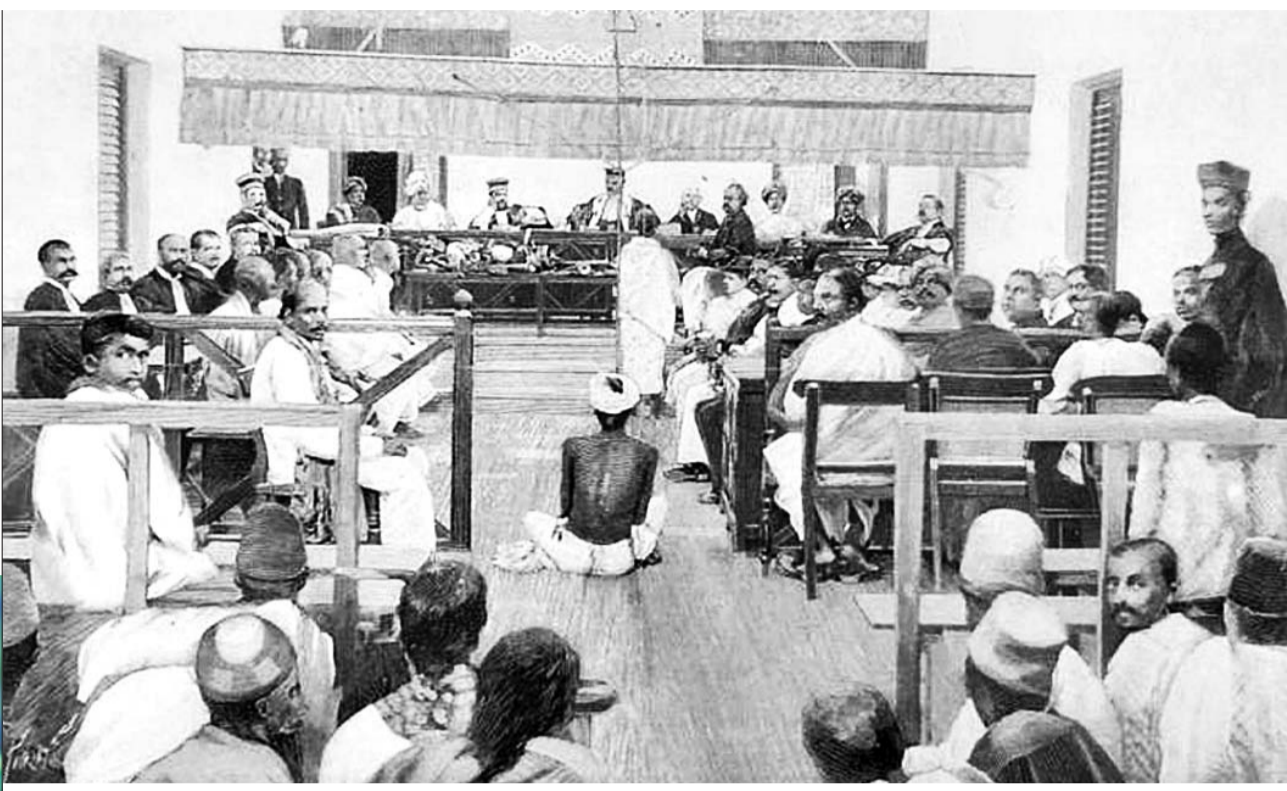
The British colonial era in India, spanning from the mid-18th century to 1947, left an indelible mark on the subcontinent's environment. While the period is often remembered for its political and economic upheavals, its ecological consequences are equally profound and enduring.

Systematic Deforestation and Habitat Loss

Under British administration, vast tracts of India's forests were cleared to meet the demands of the colonial economy. The Indian Forest Act of 1865 and its subsequent amendments, such as the Indian Forest Act of 1927, were instrumental in this process. These legislations redefined forests as state property, restricting local communities' access to resources like firewood, fodder, and timber. This not only led to widespread deforestation but also disrupted traditional livelihoods and cultural practices of indigenous communities.

Introduction of Invasive Species

In 1807, the British introduced *Lantana camara*, a thorny shrub, to India for ornamental purposes. However, this species became invasive, rapidly spreading across forests and outcompeting native vegetation. The dense thickets of *Lantana* hindered the movement of large herbivores like elephants, disrupting their feeding patterns and leading them to encroach upon human settlements, thereby escalating human-wildlife conflicts.



A photograph in a French magazine of a session of the criminal bench of the Karaikal Court in French India, in 1895. A series of ceiling punkahs are activated by the man seated on the floor.

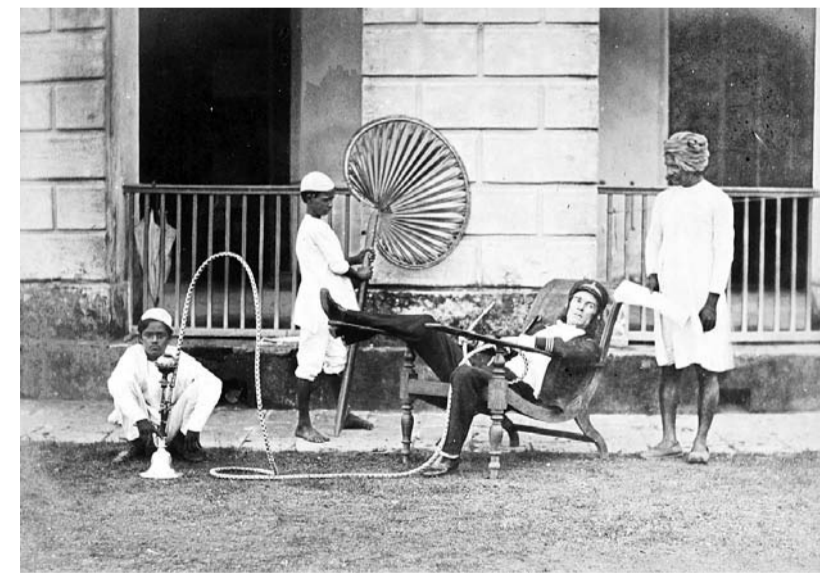


When the British first came to India, they had to adapt themselves to a lot of unfamiliar things, such as the climate, the blood-sucking mosquitoes, the spicy food, the language. But the one thing they couldn't get used to was the heat.

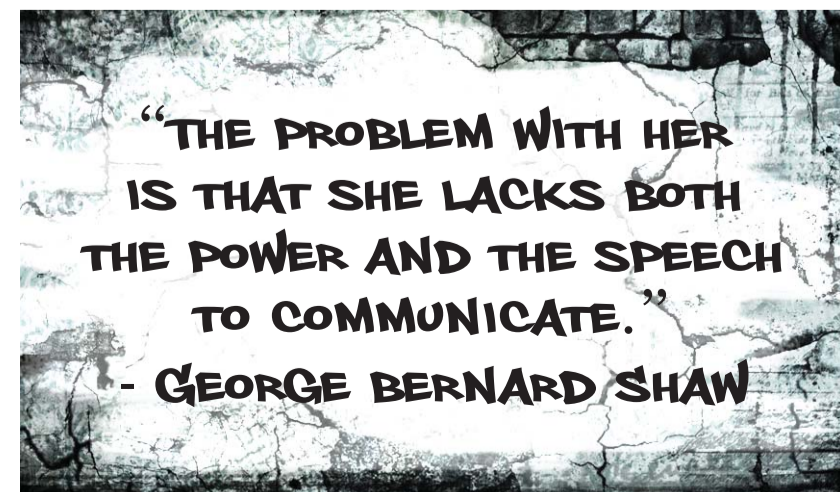
Summer in India begins from April and lasts until October. In the north and in the west, the summer arrives early. In this part of India, April and May are usually the hottest months after which the monsoon helps keep temperatures down. In eastern India and in the coastal regions, rains delay the onset of summer. But as rainfall becomes scarce, heat begins to build up, which is exacerbated by the humidity from the sea creating a very suffocating experience. The *punkah* was the life saver that made British lives at all possible in India.

Origins of the Punkah

The word *punkah* comes from the Persian word *pankha*, meaning 'fan' or 'to blow'. The device itself has a long history, dating back to at least 500 BC, when it was first used in the ancient Persian Empire. In



THE WALL



Persia (modern-day Iran), large hand-held fans made of feathers or fabric were employed to provide relief from the intense heat. These early fans were likely operated by servants or slaves, and the cooling process involved manual effort, requiring someone to wave the fan back and forth.

The British Adoption and Innovation: Fabric Panels and the Punkahwalla

As the British established themselves in India during the 18th and 19th centuries, they adopted the punkah for its practicality in combating the unbearable summer heat. The punkah's design in India became distinct from its earlier Persian counterpart. Large rectangular or square fabric panels, often made of cotton or linen, were mounted on a wooden frame, creating an efficient yet simple mechanism. These fans were typically suspended from the ceiling and attached to ropes or pulleys, which would allow a servant, called a *punkahwalla*, to pull the ropes and swing the fan back and forth, creating a breeze in the room.

The *punkahwalla* became an essential part of daily life in afflu-

ent British homes and offices in India. It was a labour-intensive job, as servants would often spend hours pulling the rope to keep the fan swinging. The presence of a punkah and a *punkahwalla* in a home became a symbol of wealth and status, as it signified that the family had the resources to employ staff to maintain such comforts.

Punkahs were a luxury found only in palatial homes and government bungalows and offices. As one British resident described, "You have a punkah over your bed, another over your bath-tub, another at your dressing-bureau, another over your dining-table, and another above your desk. Your body servant calls out to your punkah-wallah and has him shift from one cord to another as you move about your room, or go from one room to another. You have the punkah in motion all day and all night somewhere, and for this purpose, you must have two men to relieve each other. When you go to bed... you are fanned to sleep."

The Punkah in the Colonies: A Cooling Revolution

The punkah wasn't confined to just British homes in India; it became a common feature in public buildings, government offices, and even hospitals and barracks across British colonies. The cooling device played a crucial role in ensuring that colonial administrators, soldiers, and others working in tropical climates could tolerate the heat during the long, oppressive summers.

By the early 19th century, the punkah had spread beyond India and found its way to other parts of the British Empire, particularly in the colonies of the Caribbean, Africa, and Southeast Asia. In these regions, the punkah was used not only by the British colonial elite but also by local populations who had come to appreciate the cooling benefits it provided. In many cases, the fan was adapted for larger spaces, like public buildings or military barracks, and it became a familiar feature of life in the colonies.

In 1819, a significant innovation

BABY BLUES



Sweating Locals For A Colonial Comfort

PART I

Two important developments between the late-eighteenth and the mid-nineteenth century might have had particular influence in the promotion of the punkah from an item of comfort and luxury to an instrument of absolute necessity. The first of these was a possibly newly formed medical understanding since early nineteenth century concerning the European's susceptibility to the 'tropical' climate of India, that in some of its more pointed articulations, cast the punkah and similar devices as a critical factor in avoiding mortality. "Whoever cannot provide himself with these artificial cooling appliances," commented a climatological treatise, "...languish and gasp for air...Little by little, the European loses appetite and sleep...all power and energy forsake him."

#THE PUNKAH



took place in the princely state of Awadh (modern-day Uttar Pradesh, India). A steam-powered punkah was introduced, which eliminated the need for manual labour. This mechanical version was the precursor to the electric fans that would come later, and it marked a shift towards more automated cooling systems.

The Exploitation of the Punkahwalla

While the punkah provided a much-needed solution for dealing with the heat, it also became a symbol of the exploitation of colonial labour. The *punkahwalla*, often a low-ranking servant, was tasked with the physically demanding and monotonous work of operating the fan. This job, while essential for the comfort of the colonial elite, was poorly compensated,

and many *punkahwallas* worked long hours in hot, humid conditions with little regard for their well-being.

The *punkah-wallah* functioned as a "human machine," often working day and night in 12-hour shifts. They were frequently subjected to harsh, even fatal, punishment by British officers for falling asleep, notes in some accounts indicate that employers sometimes tied the puller's hair to the rope to keep them awake.

Punkah-wallahs were paid very low wages, with reports indicating they often received only a few annas per day/night. In military barracks, the hiring was handled by 'Thekedars' (contractors), who brought workers from villages, often exploiting them fur-

ther by taking a percentage of their earnings.

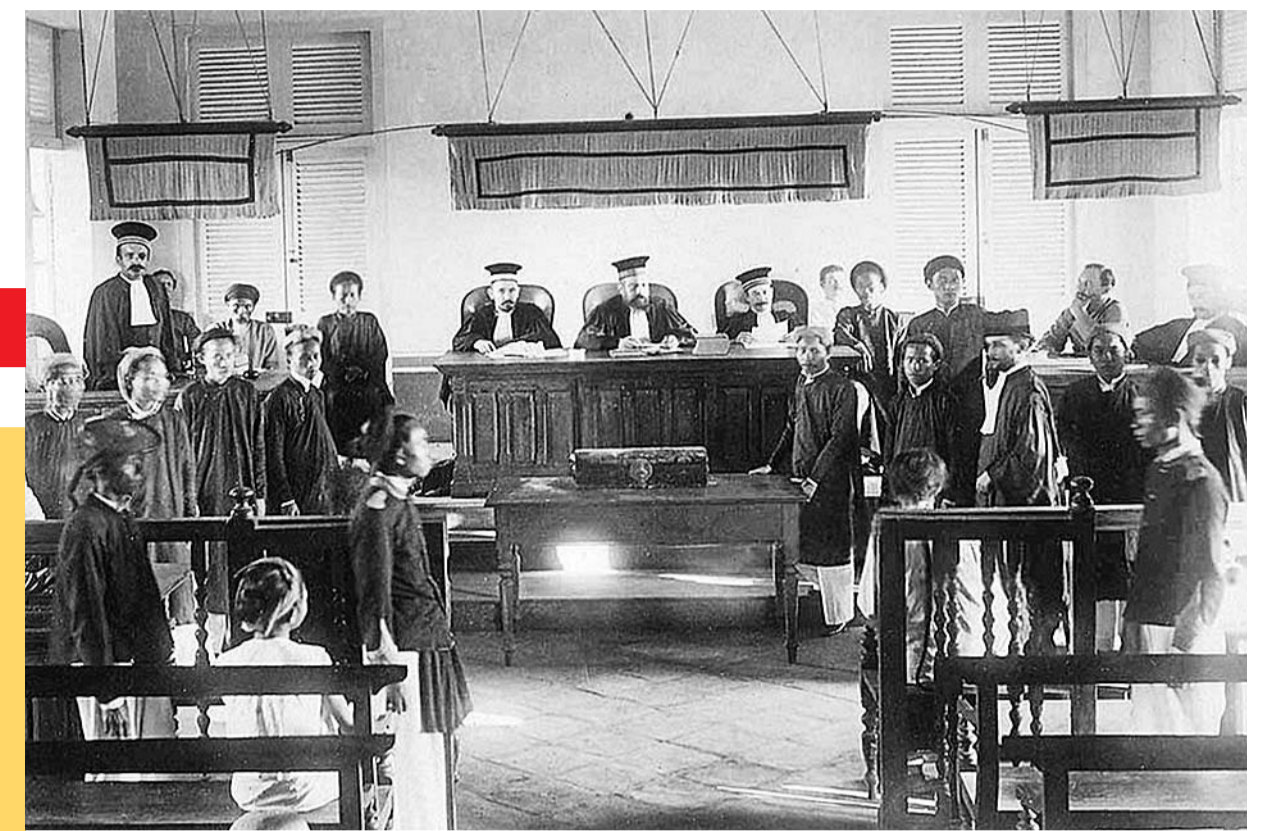
The punkah and its pullers

The traveler Peter Mundy noted the presence of 'the great artificial fan of linen which hangs down from aloft' at Shah Jahan's court in Agra where he was visiting in 1632. The Hobson-Jobson guide described an even longer lineage of the punkah, stretching back to the Arab world of the 8th century.

In the process, it discounted the apocryphal account becoming popular towards the end of the nineteenth century, that the origin of the punkah lay in an East-India Company officer's ingenious plan of hanging a table-top from the ceiling and getting his native attendant to 'swing' it above his head by tugging

at it with an attached string. Yet, it is still quite difficult to deny that colonial settlers in late eighteenth and early nineteenth century India seemed to have reinvented the use of the device on the most exaggerated scale against those mighty foes, the scorching sun and the suffocating humidity of tropical India.

There was comfort in the punkah, the kind that Justice Hyde did not have as he left the courtroom several times to change his shirt, soaking wet with perspiration, during Nanda Kumar's infamous trial in 1775. Settler Europeans' use of the punkah and its pullers, along with numerous other domestic servants, also connoted distinctive elements of 'status' and 'luxury' to metropolitan visitors. Similar distinctions, of



Punkahs were used all over South-east Asia. This photograph shows a Vietnamese court with a ceiling punkah.



course, also applied to the use of the ornate hand-held fans, which the French *voyager de Grandpre* noticed were being used individually for every attendee at the dinner table of his hosts in Calcutta. But by 1789, when he was recording these notes, these fans had already acquired their younger, and more mechanical cousin, who eventually usurped their name in future glossaries with a pride of false precedence. By 1848, one such glossary described the hand-held fan to be 'more of an ornament,' while the 'swing punkah' had apparently become an 'indispensable' fixture in 'all principal apartments' of European homes. 'The swing punkah definitely had the advantage of scale, it could fan over large or congregations and spaces and thus could be used in both private and public settings (like churches).

But still, not every European was necessarily very keen about it. Colesworthy Grant (1810-1880) maintained a difference between the way one 'may enjoy it as a relief' and the way others demand it 'as a necessity, and are unable to stir from under the punkah for an instant but in the greatest discomfort.'

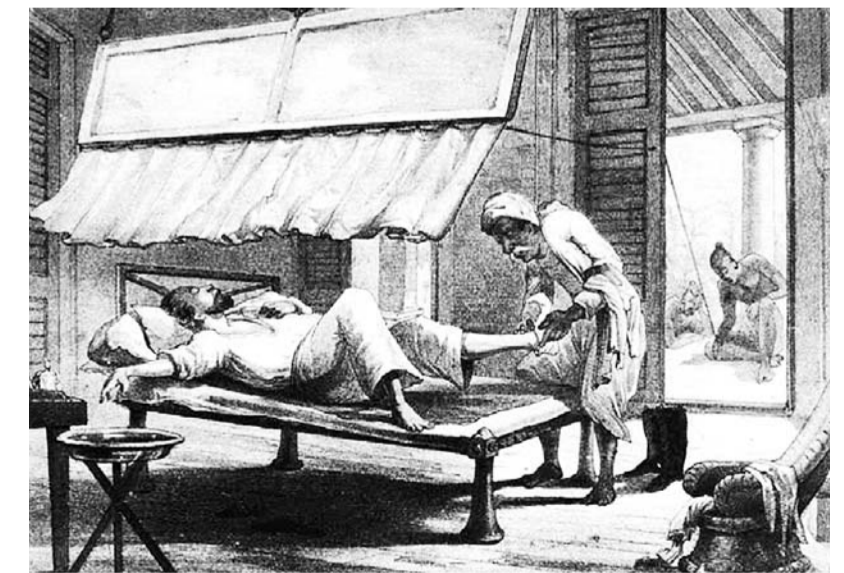
Two important developments between the late-eighteenth and the mid-nineteenth century might have had particular influence in the promotion of the punkah from an item of comfort and luxury to an instrument of absolute necessity. The first of these was a possibly newly formed medical understanding since early nineteenth century concerning the European's susceptibility to the 'tropical' climate of India, that in some of its more pointed articulations, cast the punkah and similar devices as a critical factor in avoiding mortality. "Whoever cannot provide himself with these artificial cooling appliances," commented a climatological treatise, "...languish and gasp for air...Little by little, the European loses appetite and sleep...all power and energy forsake him."

Exemplary of this new sense of alienation from the Indian climate

was the naval surgeon James Johnson's ideas. Johnson categorized the punkah and the palanquin as 'rational enjoyments' that were 'rendered necessary by the great difference between a temperate and torrid zone.' Together with them, he also classed in this category, 'the numerous retinue of domestics, and more mechanical cousin, who eventually usurped their name in future glossaries with a pride of false precedence. By 1848, one such glossary described the hand-held fan to be 'more of an ornament,' while the 'swing punkah' had apparently become an 'indispensable' fixture in 'all principal apartments' of European homes. 'The swing punkah definitely had the advantage of scale, it could fan over large or congregations and spaces and thus could be used in both private and public settings (like churches).

But still, not every European was necessarily very keen about it. Colesworthy Grant (1810-1880) maintained a difference between the way one 'may enjoy it as a relief' and the way others demand it 'as a necessity, and are unable to stir from under the punkah for an instant but in the greatest discomfort.'

Two important developments between the late-eighteenth and the mid-nineteenth century might have had particular influence in the promotion of the punkah from an item of comfort and luxury to an instrument of absolute necessity. The first of these was a possibly newly formed medical understanding since early nineteenth century concerning the European's susceptibility to the 'tropical' climate of India, that in some of its more pointed articulations, cast the punkah and similar devices as a critical factor in avoiding mortality. "Whoever cannot provide himself with these artificial cooling appliances," commented a climatological treatise, "...languish and gasp for air...Little by little, the European loses appetite and sleep...all power and energy forsake him."



migrants were notorious for their colonized character and their collective capacity to astutely bargain the conditions of their lives and livelihood.

In the domain of public transport, the Company state found it difficult to control their erratic hiring rates as well as their untimely unavailability during pilgrimage seasons. When working in private capacity as servants or palki carriers, Oriya workers, as Balthazar Solvyns noted, frequently quoted religious rules set by their chiefs in order to refuse services like lighting a tallow candle or handing a glass of water. This reluctance to conduct certain kinds of tasks in European homes extended for some time to the new requirement of punkah-pulling.

In the early nineteenth century, an observation recurs in colonial accounts about these Oriya servants, but also at times about other, possibly Muslim attendants, refusing to pull the punkah over a table serving beef or pork. In many ways then, there existed an obvious gap between a Johnson-like fantasy of tireless menial labour compensating for the heat-induced exhaustion of 'the tropics' and the realisation of this fantasy in terms of native servants systematically subjecting themselves to the gradually multiplying demands that the punkah made on their labouring time.

If this gap was eventually tided over, this had to do with a sustained campaign of the Company state towards regulating the service labour population of early-colonial Calcutta, and particularly, the 'Balasore bearers.' These Oriya migrants were policed, threatened, and subjected to strict regimes of clothing and hiring-rate control. The social and financial principles of their collective existence were ruthlessly attacked.

To be continued...

rajeshsharma1049@gmail.com

By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman

संक्षिप्त

बैठक आज

निवाड़ी। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में आयोजित आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सुबह 11 बजे अखिल हरियाणा गौड़ ब्राह्मण छात्रावास में राष्ट्रीय अध्यक्ष विरधीचंद शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। राष्ट्रीय महामंत्री सीताराम शर्मा अलियाबाद ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शंभूलाल कुईवाले, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान रामनारायण काजला, सह कोषाध्यक्ष गोपाल, बंशी बोहरा, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश मावा वाला, युवा कार्यकारी अध्यक्ष सुनिल शर्मा सहित टॉक महासभा के जिला इकाईयों के अध्यक्ष, सदस्यगण व भामाशाह भाग लेंगे। मीडिया प्रभारी लक्ष्मीचन्द शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में 51 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में सम्मेलन की व्यवस्थाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कार्यकर्ताओं को व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएगी।

संत देवानंद की पुण्यतिथि पर विशाल भंडारा

सांभरझीला। पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी देवानंद जी महाराज के परम शिष्य श्री हीरानंद जी महाराज के सानिध्य में संतों की पावन भूमि ग्राम हनुकड़ा में श्री देवानंद महाराज की 11 पुण्यतिथि के पावन मौके पर विशाल भंडारा यानी प्रसादी का आयोजन होगा। संतों का यह सम्मेलन शुक्रवार 17 अप्रैल को वैशाख कृष्ण अमावस्या पर होगा। इसी दिन भगवान शंकर मंदिर की चतुर्थ वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाई जाएगी। ठाकुर जी मंदिर से मुख्य कार्यक्रम स्थल तक सुबह 9:15 बजे महिलाओं की कलशा यात्रा बैज बाजे के साथ निकाली जाएगी। दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक सस्त्रंग होगा। टेंट एवं इवेंट समिति के सचिव हनुमान प्रसाद (चतुर्गुरिया) कुमावत व समस्त सेवा समिति के सदस्यों, भक्तगणों की ओर से संतों का सानिध्य प्राप्त करने हेतु आह्वान किया गया है। समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद जलाधारा धार्मिक आयोजन व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए है।

छात्राओं को किया जागरूक

निवाड़ी। पुलिस प्रशासन द्वारा संचालित ऑपरेशन गरिमा अभियान के तहत डीवाईएसपी रविप्रकाश शर्मा के सानिध्य में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय झिलारा में बालिकाओं को गरिमा हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्प लाइन, सिटीजन राजकोप एप, साइबर हेल्पलाइन व वृत्त सीयूजी नंबर सहित कई योजनाओं बारे में जागरूक किया। डीवाईएसपी रविप्रकाश शर्मा ने कहा कि छात्राओं को उन्हे अधिकार व कानून की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत छात्राओं को कालिका यूनिट के साथ मिलना एवं बालिका सुरक्षा संबंधी विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई। छात्राओं से यातायात नियमों व नवीन कानूनों के संबंध में भी चर्चा की गई। राजकोप सिटीजन एप पर विभिन्न विषयों पर मौजूद अवचेयनेस वीडियोज का प्रदर्शन करके छात्राओं को जागरूक किया गया।

किसान महापंचायत की बैठक आज

निवाड़ी। किसान महापंचायत की जल यात्रा को लेकर 17 अप्रैल को जिला अध्यक्ष गोपीलाल जाट की अध्यक्षता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की मौजूदगी में टॉक में जिला स्तरीय बैठक आयोजित होगी। किसान महापंचायत उपाध्यक्ष कमलेश जाट खंडवा ने बताया कि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे कृषि उपज मंडी समिति टॉक में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में निवाड़ी क्षेत्र को ईसरदा बांध का पानी नहरों द्वारा उपलब्ध करवाने को लेकर 52 ग्राम पंचायतों में पांच दिवसीय जल यात्रा निकालने, यात्रा को सफल बनाने के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन करने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया

निवाड़ी। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में कक्षा 10 वीं के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम बेटीयों में परकम लहराया है। प्रधानाचार्य सुश्रवाण चौधरी ने बताया कि कक्षा 10 में 77 छात्रों में से 40 प्रथम श्रेणी और 26 छात्र-छात्राएँ द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं।

‘कार्यवाही केवल कागज़ों तक सीमित न रहकर धरातल पर दिखाई देनी चाहिए’

खैरथल। जिला सचिवालय पर निरस्तरीय जनसुनवाई जिला कलक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 55 प्रकरण प्राप्त हुए जिनकी सुनवाई कर जिला कलक्टर ने अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने, पेयजल की सप्लाई सुचारु कराने, पानी को बहाव को रोकने हेतु नाला बनवाने, फर्जी पट्टा जारी करने, पीएम आवास योजना के तहत बने मकान की जिओ टैगिंग कर नरंगा भुगतान करवाने, इंतकाल खुलवाने, भूमि अवापत का मुआवजा दिलाने, खेत से रास्ता खुलवाने, सड़क ,आवासीय पट्टा बनवाने, नामांतरण,



खैरथल जिला सचिवालय पर जिला कलक्टर ने अधिकारी, जनप्रतिनिधि के साथ जनसुनवाई की।

पथरगढी, शमशासन से अतिक्रमण हटाने, जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। कलक्टर ने अधीक्षण अभियंता पीएचईडी को परिवादी के क्षेत्र बंबोरा में जाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर

समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। पीएम सम्मान निधि योजना एवं पेंशन योजना के लाभार्थियों को मौके पर उनका वेरिफिकेशन करवाकर योजना का लाभ दिलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यवाही

खैरथल जिला सचिवालय पर हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई, विधायक दीपचंद खेरिया सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे मौजूद

केवल कागज़ों तक सीमित न रहकर धरातल पर प्रभावी रूप से दिखाई देनी चाहिए। साथ ही आगामी साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निस्तारित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों द्वारा किए गए निस्तारण की गुणवत्ता कैसी रही तथा परिवादी के कार्य का वास्तविक रूप से समाधान हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नवाहन के अनुरूप आमजन को अधिक से अधिक राहत देने के लिये सभी विभाग-अधिकारी मिलकर काम करें ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन लाभान्वित हो सके।

सार-समाचार

दीप यज्ञ का आयोजन



राजगढ़। स्टेशन मार्ग स्थित कीर्ति नगर कॉलोनी में गायत्री शक्तिपीठ की ओर से दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने उपस्थित दर्ज कराकर विश्व शांति का संदेश दिया। महिलाओं ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ दीप यज्ञ को सफल बनाया एवं भाईचारा, प्रेम एवं सद्भाव के साथ विश्व कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान मुख्य प्रबंधक टुस्टी मीना खंडेलवाल की ओर से गायत्री परिवार की ओर से किए जाने वाले दीप यज्ञ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिलाओं ने सिर पर थाली में दीप जलाकर दीपोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर सुनीता शर्मा, रश्मि विजय, मीना विजय, रितिका शर्मा, कृपा शर्मा, मिथलेश शर्मा, किरण शर्मा, कृष्णा, धनबाई, प्रिगिता अन्जु सचदेवा, विमला मारोटिया एवं अन्य परिजन मौजूद रहे। रितिका शर्मा का बाल संस्कार को लेकर किए गए सार्थक प्रयासों पर दुःखी पहना कर स्वागत किया गया। इस दौरान भारी संख्या में गायत्री परिवार से जुड़ी महिलाएँ मौजूद रही।

रक्तदान शिविर आयोजित



कोटपतली। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को यहां के राजकीय बीडीएम जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह व एसपी नाजिम अली खान के नेतृत्व में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा बह-चढ़कर भाग लेते हुये कुल 43 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं शिविर में कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष व पूर्व पार्षद तारा पूतली के नेतृत्व में 11 युवाओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान कर अपना योगदान दिया गया। इस दौरान भूपसिंह पुतली, आर्यन चौधरी, योगेश ठेकेदार, देशराज अर्वा, आशीष खंडा, गजेन्द्र मीणा, रूप स्वामी, सच्ची गुर्जर टोटा, सुनील वामी पावटा समेत अन्य मौजूद रहे।

उपखंड अधिकारी को निमंत्रण सौंपा

पावटा। आगामी 19 अप्रैल रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में आयोजक समिति ब्राह्मण महासभा पावटा द्वारा पावटा उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा को औपचारिक रूप से निमंत्रण पत्र सौंपकर कार्यक्रम में पधारने का आग्रह किया गया। ब्राह्मण महासभा पावटा पदाधिकारियों अध्यक्ष सुरेश न्यायावी, उपाध्यक्ष दीपक पटेल, गिरिराज बोहरा, महामंत्री विष्णु पटेल, कोषाध्यक्ष ललित शर्मा, प्रचार मंत्री मोहन गौड़, सदस्य विपिन शर्मा, मोहित शर्मा ने उपखंड अधिकारी पावटा निवास पहुंचकर उन्हें भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभायात्रा, पूजा-अर्चना सहित कई आयोजन किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा ने आयोजन की सहायता करते हुए कहा कि इस प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरपूर आग्रह किया। आयोजक समिति के सदस्यों ने सभी क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

आग लगने से चाय के खोखे में हजारों का नुकसान

पावटा। क्षेत्र के टसकोला गांव निवासी एक व्यक्ति के चाय के खोखे में देर रात अचानक आग लगने से हजारों रुपये का नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार टसकोला निवासी फुलचन्द यादव पुत्र जगदीश यादव ने प्रगुपूर में रिपोर्ट देकर बताया कि उसने चकतर्ष गौशाला के पास चाय-पानी का खोखा व झोपड़ो डाल रखी है, जिससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। पीड़ित दुकानदार फूलचंद यादव के अनुसार 16 अप्रैल की देर रात करीब 2:30 बजे अचानक उसके खोखे में आग लग गई। उस समय वह वहीं सो रहा था। आग की लपटें देख उसकी नींद खुली, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और खोखे में रखा सामान जलकर आग हो गया। आगजनी की इस घटना में खोखे में रखा सोल्ड ट्रिंक का सामान करीब 30 हजार रुपये का, प्लास्टिक की 5 कुर्सियां, 2 चारपाई, लकड़ी का कांटेटर सहित अन्य घरेलू व दुकान का सामान पूरी तरह जल गया। पीड़ित ने कुल 55 से 60 हजार रुपये के नुकसान की आशंका जताई है। पीड़ित ने पुलिस थाना प्रगुपूर में रिपोर्ट दर्ज करवाकर मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

समाजसेवी सुरेश शर्मा का निधन

पावटा। कस्बे के लिए अत्यंत दुःखद समाचार सामने आया है। सुरेश शर्मा का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई और सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। सुरेश शर्मा ब्राह्मण महासभा पावटा के संरक्षक होने के साथ-साथ आदर्श रामलीला मंडल पावटा संरक्षक के रूप में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। वे समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय थे और हमेशा सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण तथा धार्मिक आयोजनों में अग्रणी भूमिका निभाते थे। उनका जीवन समाजसेवा के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों एवं जनहित के कार्यों में बह-चढ़कर भाग लिया और युवाओं को भी समाज के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उनके सादगीपूर्ण जीवन, विमल स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के कारण वे सभी के प्रिय थे। जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करने लगे।

सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालक परेशान

अलवर। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जुली ने राज्य सरकार से कुशालगढ़ तिराहे से थैक यू बोर्ड वाया भर्तूरि सड़क निर्माण कार्य और भर्तूरि तिराहे की पुलिया के जीर्णोद्धार की घोषणा करवाकर राज्य सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि सड़क मार्ग पर पुलिया अत्यंत जर्जर स्थिति में है जिससे आमजन और श्रद्धालुओं को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने बताया कि आगामी 17 से 20 सितंबर 2026 को महाराजा श्री भर्तूरि एवं पांडुपोल हनुमान जी महाराज का वार्षिक मेला आयोजित होगा जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु आगे पिछले वर्ष मेले में भारी वर्षा के कारण भर्तूरि पुलिया पर ओवरफ्लो से प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था में भारी मशकत करनी पड़ी और आवागमन भी बाधित हुआ था यह सड़क मार्ग अलवर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल भर्तूरि धाम एवं पांडुपोल हनुमान जी धाम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है। उन्होंने बताया कि जनहित सुधार एवं आगामी मेले को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर अतिविवेक प्रारंभ किया जाना चाहिए।

जयपुर ग्रामीण में पुलिस दिवस समारोह में 129 पुलिसकर्मी सम्मानित

जयपुर। जिला जयपुर ग्रामीण पुलिस की ओर से पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन में भव्य पुलिस दिवस समारोह 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 129 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा चिन्ह, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण हनुमान प्रसाद ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज राहुल प्रकाश रहे। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) रजनीश पुनिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत सेरेमोनियल परेड से हुई। जिसमें मुख्य अतिथि ने सलामी दी। इसके बाद पुलिस जवानों द्वारा



पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा चिन्ह, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। पुलिस बैड की मधुर धुनों के बीच जवानों ने अनुशासन और दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया, जिसने उपस्थित जनसमूह को प्रभावित किया। इसके अलावा वर्ष 2025 में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया।

जिनमें 70 पुलिसकर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह, 37 को अति उत्तम सेवा चिन्ह और 22 को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए गए। इसके साथ ही पुलिस की सहायता करने वाले 7 नागरिकों को भी साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य

समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज राहुल प्रकाश व विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पुनिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे

अतिथि द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निष्पक्ष, संवेदनशील और जवाबदेह पुलिसिंग के लिए प्रेरित किया गया।

नशे में वाहन चलाने वालों पर शिकंजा, 17 गिरफ्तार, 55 ई-रिक्शा जब्त

भरतपुर। जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देशानुसार जिले में कानून व्यवस्था, शांति एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा सख्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार में स्टंट करने, सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचा सकने तथा यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी रहेगी।

पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में नशे की हालत में वाहन चलाने, शांति भंग करने और उत्पात मचाने वाले कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पहचान के लिए ब्रेथ एनालाइजर का व्यापक उपयोग किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तेज गति, रेस ड्राइविंग और सड़क पर स्टंट करने वालों पर भी लगातार गिरफ्तारी रखी जा रही है। कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस का कहना है कि यह अभियान आमजन की सुरक्षा और सड़क हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से

शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पहचान के लिए ब्रेथ एनालाइजर का व्यापक उपयोग किया

चलाया जा रहा है। इसके साथ ही भरतपुर शहर के मुख्य बाजार में जागू की समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। यातायात प्रभारी अजय सिंह के नेतृत्व में कुम्हरे गेट से बिजलीघर तक कार्रवाई करते हुए 55 ई-रिक्शा जब्त किए गए तथा चालान काटे गए। पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों को निर्धारित मार्ग एवं स्टैंड का पालन करने के निर्देश दिए। यातायात पुलिस ने कहा कि बाजार क्षेत्र में लावारिस रूप से ई-रिक्शा खड़ा करना, गलत दिशा में चलाना या नियमों के विरुद्ध संचालन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बार-बार चेतावनी देने के बावजूद नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

5 आरोपी गिरफ्तार

लालसोट। फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर की हत्या के मामले में लालसोट पुलिस ने आखिरकार बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को धर दबोचा है। इतना ही नहीं, वारदात में सहयोग करने वाले 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि अभी भी कुछ नामजद आरोपी पुलिस को पकड़ से बाहर हैं। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। विनोद कुमार सौपा के निर्देशन में पुलिस टीम लगातार दबिशा दे रही थी, वहीं एसपी सागर राणा खट्टे पूरे मामले को माॉनिटरिंग कर रहे हैं। जांच अधिकारी दिलीप मीणा ने साफ कहा है कि अपराधियों की मदद करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल को हिस्ट्रीशीटर धर्मेश उर्फ फौजी मीणा की फायरिंग में हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था।

‘शहरी और ग्रामीण वार्डों के विकास के लिए सुझाव भेजें’

भरतपुर। जिला कलक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान की प्रगति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान राज्य के सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2047 तक के विजन के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र का डायनेमिक मास्टर प्लान तैयार करना है, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 20 अप्रैल तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में फोकस ग्रुप डिस्कशन आयोजित कर आमजन से सुझाव प्राप्त किए जाएं। इसके बाद 25 अप्रैल तक ग्राम सभा एवं वार्ड सभा द्वारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान का अनुमोदन किया जाए तथा 30 अप्रैल तक इसे पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 15 मई तक हर हाल में सभी पंचायतों एवं वार्डों के फाइनल मास्टर

अभियान का उद्देश्य वर्ष 2047 तक के विजन के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र का डायनेमिक मास्टर प्लान तैयार करना है

प्लान तैयार कर अपलोड किए जाएं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड का जीआईएस आधारित बेस मैप तैयार किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवार आवश्यकताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके। स्थानीय निवासियों, महिलाओं और युवाओं के सुझावों के आधार पर जल निकासी, सड़क, आवागमन, रोशनी जैसी समस्याओं के समाधान का रोडमैप बनाया जाएगा। इसका साथ ही डिजिटल माॉनिटरिंग और जियो-टैगिंग के माध्यम से विकास कार्यों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। स्कूलों में पानी और बिजली की व्यवस्था, सामुदायिक भवन, पार्क में ओपन जिम, सीसीटीवी कैमरे तथा स्ट्रीट लाइट जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला कलक्टर ने बताया कि

अभियान में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से नागरिक सीधे अपने सुझाव मास्टर प्लान में शामिल कर सकेंगे। साथ ही शहरी वार्डों में सुझाव पेटियां भी स्थापित की गई हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईटी विभाग के माध्यम से क्यूआर कोड फीडबैक सिस्टम शीघ्र विकसित किया जाए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आईटी मैपिंग कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के लिए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और सुरक्षा सहित 11 सेक्शन में डिजिटल बेसलाइन तैयार की जा रही है। इसी आधार पर अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए अधिक से अधिक सुझाव निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराएं, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सशक्त और प्रभावी मास्टर प्लान तैयार किया जा सके।

नमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया

निवाड़ी। सकल दिगम्बर जैन समाज के तत्वावधान जैन आचार्य इन्द्रनदी महाराज ससंध के सानिध्य में श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अग्रवाल मंदिर सहित सभी जिनालयों में जैन धर्म के 21 वें तीर्थंकर नमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ मनाया गया। मीडिया प्रभारी

‘भगवान नमिनाथ का कल्याणक उनकी अहिंसा, त्याग और वैराग्य की परकाष्ठा का प्रतीक है’

सुनिल भाणजा व हितेश छावडा ने बताया कि प्रातःकाल आचार्य संध के सानिध्य में भगवान का अभिषेक, पंचामृत अभिषेक एवं शांतिधारा की गई। इस दौरान पूजा-अर्चना करके उत्साह पूर्वक भगवान के समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाया गया।



नमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू चढ़ाते हुए श्रद्धालु।

इसी प्रकार श्री सहस्त्रकृत विज्ञातीर्थ पर आर्यिका ज्ञानश्री माताजी ससंध के सानिध्य में भगवान का मोक्ष कल्याणक श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आचार्यश्री ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह

कल्याणक आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया है। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का पालन करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए। अटों कर्मों का सम्पूर्ण नाश एवं रागद्वेष को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त

किया जा सकता है। भगवान नमिनाथ का कल्याणक उनकी अहिंसा, त्याग और वैराग्य की परकाष्ठा का प्रतीक है। मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य होता है। उन्होंने कहा कि मोक्ष कल्याणक जन्म मृत्यु के बंधन से शाश्वत मुक्ति का प्रतीक है।

हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस के स्थापन दिवस समारोह में कहा कि दो वर्ष में अपराधों में 18.77 प्रतिशत कमी आई है

जयपुर, 16 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाकर प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है तथा हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शर्मा गुरुवार को राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर अवसर पर

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कम्प्यूटि पुलिसिंग से साइबर अपराध, नशा व संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। इनसे निपटने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया और परेड ग्राउंड में सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया।

समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटि पुलिसिंग से साइबर अपराध, नशा व संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले दो वर्षों में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में 25.68 प्रतिशत, डकैती में 47.26,

लूट में 50.75 तथा महिला अत्याचारों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड में आयोजित सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बीजू जॉर्ज जोसफ व विपिन कुमार पाण्डेय, पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार, उपनिरीक्षक सीताराम भाकल व गिरधारी लाल शर्मा तथा सहायक उपनिरीक्षक गोविंदराम को मुख्यमंत्री उल्लूक्य सेवा पदक से पुरस्कृत किया।

मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए नया पोस्टल एण्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इससे पहले उन्होंने

परिसर में शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता के विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100-100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों का निर्माण किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस कार्मिकों के स्पेक्ट्रम, वेल्फेयर एवं उत्सव फंड में 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों के लिए प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों के निर्माण की भी घोषणा की।

प्र.मंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने फोन पर बात की

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत और फ्रांस ने एक बार फिर दुनिया को अपनी रणनीतिक साझेदारी का अहसास कराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने करीबी मित्र इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात की। इस बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु न केवल क्षेत्रीय शांति रही, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई गई।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा और नौबंद की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल किया जाना अनिवार्य है। दरअसल, यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है और यहां किसी भी तरह का अवरोध दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है।

‘अमेरिका की छूट खत्म होने के बाद भी रुस से तेल खरीदते रहेंगे’

भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील से पहले बड़ा ऐलान किया

■ **सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा रुस से तेल खरीदने के कारण ही भारत के पास 60 दिनों का तेल भंडार है।**

हरिद्वार में आयोजित हो रहे हैं और पहले भी ऐसी स्थिति में भारत ने स्वतंत्र निर्णय लिया था। अभी भी वॉशिंगटन को मनाने की कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हर्दीप सिंह पुरी ने अमेरिका के राष्ट्रपति सर्जियो मारे से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिकी तेल-प्लंपीजी आयात बढ़ाने और रूसी तेल की निरंतर आपूर्ति पर एकलौट चर्चा हुई। इसके ठीक कुछ दिन पहले, विदेश सचिव विक्रम मिसरी की

हलिया वॉशिंगटन यात्रा के दौरान भी इन मुद्दों पर गहन विमर्श हुआ था, जहां मिसरी ने अमेरिका-भारत ऊर्जा साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर दिया। अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मौजूदा पश्चिम एशिया संकट में भारत की कच्चे तेल की विशाल जरूरत को रूस के अलावा अभी और कोई देश पूरा नहीं कर सकता। एक अधिकारी के मुताबिक, ईरान हमले की शुरुआत से पहले तक भारत अपनी जरूरत का 60 फीसद तक कूड

होर्मुज जल मार्ग के रास्ते ला रहा था।

अब यह रास्ता बंद है। इराक व कुवैत से आपूर्ति एकदम ठप है। यूएई व सऊदी अरब से आपूर्ति सीमित हो चुकी है। इन देशों से आपूर्ति कब सामान्य होगी, यह अनिश्चित बना हुआ है। रूस से भारी पैमाने पर आयात करने की वजह से ही भारत के पास अभी भी 60 दिनों का पेट्रोलियम भंडार है।

ऐसे में रूस से तेल खरीद पर रोक लगाना भारत के लिये संभव नहीं है। रूस से तेल खरीदने का कोई सरकारी डाटा तो नहीं है लेकिन निजी एजेंसी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लोनिक (सीआरईए) के अनुसार भारत की ताजा रिपोर्ट बताती है कि रूसी कच्चे तेल का आयात मार्च, 2026 में दोगुना होकर 2.06 मिलियन बैरल प्रति दिन बढ़ गया है, जबकि फरवरी 1.06 मिलियन बैरल रोजाना की खरीद हुई थी।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को कांग्रेस ने सस्पेंड किया

■ **कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेन्द्र सिंह ने कहा इन विधायकों ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा था**

■ **इससे पूर्व इन विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर निलम्बन की कार्यवाही की गई।**

मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस ने नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, सादौरा विधायक रणु बाला, पुन्हा विधायक मोहम्मद इलियास, हथौन सीट से विधायक मोहम्मद इस्मइल और रतिया से विधायक जनेल सिंह पर पार्टी की आधिकारिक लाइन का

उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। प्रदेश कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति (डीएससी) ने हाल ही में पांच विधायकों के निलम्बन की सिफारिश की है। समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने पूर्व में कहा था कि समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की है और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के पक्ष में पांच

पार्टी विधायकों की ओर से कथित 'क्रॉस-वोटिंग' के मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व को अपना निर्णय बता दिया है। समिति ने विधायकों को निर्लेखित करने की सिफारिश की थी। डीएससी ने विधायकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों के जवाबों की जांच की।

इससे पहले, कांग्रेस ने हरियाणा के अपने पांच विधायकों को 'क्रॉस-वोटिंग' के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के पक्ष में जानबूझकर मतदान न करके दल-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

रूस और ईरान से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बुधवार को पत्रकारों से कहा, "हम रूसी तेल पर सामान्य लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेंगे, और न ही ईरानी तेल पर। यह वह तेल था, जो 11 मार्च से पहले समुद्र में था, इसलिए वह सब उपयोग में आ चुका है।"

ये अस्थायी छूट बढ़ती ऊर्जा कीमतों को स्थिर करने के लिए अल्पकालिक उपाय के रूप में दी गई थीं, जिनके तहत निर्धारित समय सीमा से पहले जहाजों पर लोड किए गए तेल के सीमित लेन-देन को वैश्विक बाजार तक पहुंचने की अनुमति दी गई, ताकि युद्ध के दौरान ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव कम किया जा सके।

इन छूटों को न बढ़ाने का फैसला

ऐसे समय आया है, जब वॉशिंगटन, ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति को अभी मजबूत कर रहा है। रूसी तेल की खरीद पर दी गई छूटों ने भारत को वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति सुरक्षित करने में मदद की। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों ने इस अवधि में लगभग 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर दिए।

रिलायंस सहित, प्रमुख रिफाइनरियों ने इस वर्ष जनवरी में अमेरिकी दबाव के कारण रोसेनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूसी कंपनियों से खरीद कम कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए फिर से रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी।

चीन व ईरान के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की

बीजिंग/तेहरान, 16 अप्रैल। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच चीन और ईरान के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र में जारी संघर्ष, युद्धविराम और शांति वार्ताओं पर विस्तार से चर्चा की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि संघर्ष विराम और संवादा की प्रक्रिया को बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही ईरानी जनता के मूल हितों के अनुरूप है और क्षेत्रीय व वैश्विक समुदाय की साझा अपेक्षाओं को भी दर्शाता है।

‘मतदान से दो दिन पहले भी मिली क्लिनि चिट तो दे पाएंगे वोट’

सुप्रीम कोर्ट ने प.बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ी घोषणा की

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव से ठीक पहले तक अपीलीय ट्रिब्यूनल से मंजूरी पाने वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा चुनाव से दो दिन पहले तक मंजूर किए जाएंगे, उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति होगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 21 अप्रैल या 27 अप्रैल 2026

■ **प.बंगाल की मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया व लोगों से कहा कि मताधिकार की प्राप्ति के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करें।**

तक अपीलीय आदेशों को लागू करते हुए एक पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए, ताकि योग्य नागरिकों को मतदान से वंचित न होना पड़े।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों की अपील लंबित हैं, उन्हें केवल इसी आधार पर मतदान का अधिकार वापस नहीं दिया जाएगा, यानी अपील प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा की गई यह पूरी जांच प्रक्रिया बेहद

सूचीतीपूर्ण रही है, जिसे कम समय में पूरा करना वास्तविक रूप से कठिन कार्य था। कोर्ट ने यह भी बतावनी दी कि अपीलीय स्तर पर आपत्तियों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को दोबारा खोलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया बाधित न हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करना चाहिए।

तृणमूल विधायक अब्दुर रजाक ने पार्टी छोड़ी

मुर्शिदाबाद, 16 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से केवल सात दिन पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुर्शिदाबाद जिले की जालंगी विधानसभा सीट से वरिष्ठ विधायक अब्दुर रजाक मंडल ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उनके इस फैसले से चुनावी माहौल में सरगामी बंद गई है। रजाक मंडल लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे और स्थानीय स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है।

अब्दुर रजाक मंडल ने जालंगी के कांटाबाड़ी स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान उन्होंने एलान किया वे अब टीएमसी के साथ नहीं लगे हैं। उन्होंने रानीनगर से टीएमसी उम्मीदवार सौमिक हुसैन पर निशाना साधा।

नीतीश के उदाहरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को कमजोर करने या तोड़ने के लिए "यूज एंड थ्रो" की नीति अपनाती है। इसके उदाहरण के रूप में शिवसेना, असम गण परिषद, शिरोमणि अकाली दल, एआईएडीएमके, एलजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी जैसे दलों के विभाजन या कमजोर होने का हवाला दिया जाता है।

करीब 76 वर्ष के नायडू को आश्चर्य है कि यदि स्पष्ट उत्तराधिकार योजना नहीं बनाई गई, तो टीडीपी का भी यही हाल हो सकता है। बिहार की घटनाओं की पृष्ठभूमि में, उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से धीरे-धीरे अलग करना शुरू कर दिया है। साथ ही, नारा लोकेश के करीबी सहयोगियों को भी अहम पद दिए गए हैं। कितलाव राजेश को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और सना सतीश को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।

नायडू ने पार्टी के पोलिट ब्यूरो, राष्ट्रीय और राज्य समितियों में बड़े

बदलाव किए हैं, जिनके तहत, कई वरिष्ठ नेताओं को प्रतीकात्मक भूमिकाओं में सीमित कर दिया गया है। सोमि रेड्डी, चंद्र मोहन रेड्डी, बांडा उमाहेश्वर राव, कन्ना लक्ष्मी नारायण, कला वेकट राव और कृना रवि कुमार जैसे नेताओं को कम प्रभाव वाले पद दिए गए हैं।

नायडू के ये कदम नीतीश कुमार प्रकरण के असर के रूप में देखे जा सकते हैं। साथ ही, इसे भाजपा के विस्तारवादी रुख को लेकर उनकी आशंकाओं से भी जोड़कर देखा जा सकता है। वैसे भी, वे ही क्षेत्रीय दल टिके रहे और प्रासंगिक बने रहे हैं, जिन्होंने समय रहते उत्तराधिकार की योजना तय कर ली, जैसे बिहार में आरजेडी, तमिलनाडु में डीएमके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तेलंगाना में बीआरएस और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी। वहीं, बीएसपी और बीजेडी जैसे दलों ने अभी तक स्पष्ट उत्तराधिकार योजना नहीं बनाई है।

महिला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिनिधित्व से वंचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी आबादी का लगभग 50 प्रतिशत है और उन्हें उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि महिला आरक्षण विधेयक को नई जनगणना के साथ क्यों नहीं लाया जा रहा, जो ओबीसी की सही तस्वीर पेश करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस और भाजपा जाति जनगणना के नए आंकड़ों से डर रहे हैं, जो ओबीसी के लिये उनका सही हिस्सा सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में है, लेकिन ओबीसी, दलित और आदिवासी महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पिछड़े वर्गों के आंकड़े शामिल नहीं हैं, और यह ईमानदारी नहीं है।

एक तरफ ट्रंप वार्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समझौते के कोई संकेत नहीं दे रहा है। ईरान अपने अनुसार यूरेनियम संवर्धन करने के अधिकार पर अड़ा हुआ है। अमेरिका ने अपने प्रस्ताव में 20 वर्षों तक ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन न करने की बात कही थी।

इरान ने सुझाव दिया है कि वह केवल पाँच वर्षों तक संवर्धन कार्यक्रम रोकने के लिए तैयार हो सकता है। इसके अलावा, संवर्धन की सीमा पर भी सहमति नहीं बन पाई है। पहले एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत ईरान को 3.67 प्रतिशत तक संवर्धन की अनुमति थी। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के पास पहले से ही 60 प्रतिशत से अधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार है।

अपने आक्रामक रुख का विस्तार करते हुए, हेग्रेस ने कहा कि अमेरिका एक ओर स्ट्रेट की सैन्य नाकाबंदी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर

“ऑपरेशन प्युरी” नामक एक नया आर्थिक अभियान भी चला रहा है, जो सैन्य विकल्प का आर्थिक स्वरूप है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट अब ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए एक व्यापक आर्थिक युद्ध कार्यक्रम को ऑपेराचरि कर रहे हैं। ईरान पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है, उसके प्रमुख उद्योग प्रभावित हैं, व्यापार घट चुका है और तेल राजस्व में भारी कमी आई है। इसके बावजूद, ईरान ने अपने लोगों की कठिनाइयों के बीच भी संघर्ष जारी रखा है।

अमेरिका की रणनीति अब यह है कि आंतरिक आर्थिक दबाव बढ़ाकर देश में विरोध और असंतोष को उकसाया जाए, जिससे शासन पर दबाव बने। हालांकि, यह एक पश्चिमी दृष्टिकोण है, और ईरान ने कई बार दिखाया है कि वह इस तरह के दबाव के आगे आसानी से नहीं झुकता।

इज़रायल व लेबनान में दस दिन का सीज़फायर

34 सालों में पहली बार दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है

■ **इस बैठक की मेजबानी अमेरिका ने की है। ट्रंप ने इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया व कहा कि हम इस सीज़फायर को स्थाई शांति में बदलना चाहते हैं।**

दुनिया भर में नौ युद्धों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है और यह मेरा 10 वां लक्ष्य होगा, तो चलिए इसे पूरा करते हैं। बताया जा रहा है कि लेबनान की ओर से यह साफ संदेश दिया गया था कि जब तक जमीनी स्तर पर संघर्ष विराम लागू नहीं होता, तब तक किसी भी तरह की सीधी बातचीत संभव नहीं है। इस रुख के बाद कूटनीतिक प्रयास तेज हुए और अंततः दोनों देशों ने सीज़फायर पर सहमति जताई। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के प्रतिनिधि 34 वर्षों में पहली बार

वॉशिंगटन डीसी में आमने-सामने मिले। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रबियो भी मौजूद रहे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति और सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस अस्थायी सीज़फायर को स्थायी शांति में बदलने के लिए दोनों देशों के साथ काम करें। इससे पहले मंगलवार को अमेरिका ने इज़रायल और लेबनान के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की, जो 1993 के बाद पहली उच्च-स्तरीय पहल थी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस

बैठक में प्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने, युद्धविराम लागू करने, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और व्यापक शांति ढांचे की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी।

सरकार अभी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार मतदान के लिए जोर देकर यह नैटिव बनाया चाहती है कि कांग्रेस और विपक्ष महिला विरोधी है, या फिर वह विधेयक वापस ले ली? संभावना यही है कि सरकार मतदान करवाने पर जोर देगी, भले ही उसे सदन में हार का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन कुछ विपक्षी दलों को अपने पक्ष में लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रयास ज्यादा सफल होते नहीं दिख रहे हैं।

राज्यसभा के निर्विरोध उपसभापति बनेंगे हरिवंश

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने निर्वाचन प्रक्रिया से विपक्ष के अलग रहने की घोषणा की

■ **वरिष्ठ जद यू नेता तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बनेंगे।**

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। राष्ट्रपति की ओर से नामित हरिवंश ने गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय में उपसभापति पद के लिए नामांकन किया। वे जनता दल (यू) से सदन में दो बार निर्वाचित एवं दोनो बार राज्यसभा के उपसभापति रहे हैं। राज्यसभा में कल उपसभापति का निर्वाचन होगा। विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर आपत्ति जाहिर करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया निरादर करने का कोई इरादा नहीं है। विपक्ष को उम्मीद है कि हरिवंश अपने तीसरे कार्यकाल में विपक्ष के अनुरोधों के प्रति अधिक सहिष्णु और ग्रहणशील होंगे। जयराम रमेश ने तीन अप्रतिहतता जताई हैं। उनका कहना है कि 7 सालों से लोकसभा

में उपाध्यक्ष का पद खाली है। राज्यसभा में राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किसी व्यक्ति पर इससे पहले कभी भी उपसभापति पद के लिए विचार नहीं किया गया है। वहीं, उन्हें तीसरी बार मौका देते समय विपक्ष से विचार विमर्श भी नहीं किया गया। पिछले माह राष्ट्रपति ने हरिवंश को राज्यसभा का सदस्य नामित किया था। हरिवंश नारायण सिंह का 9 अप्रैल को उपसभापति के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो गया। तब से यह पद खाली है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन का संचालन करते हैं।